प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 37 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 18 जून 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

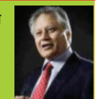

असफल लोग दो तरह के होते है। पहले वे जो करते तो है, लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो है पर कुछ करते नहीं।

शिव खेड़ा

शिवराज के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे दिग्विजयसिंह

भोपाल एजेंसी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर एक साल पहले ?कथित तौर पर फर्जी वीडियो ट्वीट करने के मामले में शिकायत की है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की शिकायत पर मुझ पर और 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर के नाम पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि जब तक वीडियो कहां से आया, किसने एडिटिंग किया है यह प्रमाणित न हो जाए, बीजेपी की किसी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए बताया कि श्जैसा मैंने कहा था आज मैंने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर, कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, आरिफ अकील और पीसी शर्मा के साथ अपराध शाखा थाना भोपाल जा कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

इससे पहले दिग्विजय ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि वह चौहान के खिलाफ फेक वीडियो ट्वीट करने के मामले में उसी थाने पर एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, जिस थाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने बीजेपी नेता गए थे।

पिछले दिनों चौहान ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके फेक बताते हुए सिंह ने इस मामले में सीएम चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सिंह ने चौहान के पुराने वीडियो से छेड़छाड़ कर बनाया गया नौ सैकंड का वीडियो ट्वीट किया था। इसके बाद भाजपा नेताओं ने यहां पुलिस की अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटनाक्रम के उपरांत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

नियम कायदों को ताक में रख पैसों के दम पर की गई आंगनवाड़ी में फर्जी नियुक्ति

कांग्रेस राज में रखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की नींव को भाजपा सरकार ने सींचा

गूंज का बड़ा खुलासा, चयनित को हटाकर अपात्र की कर ली भर्ती

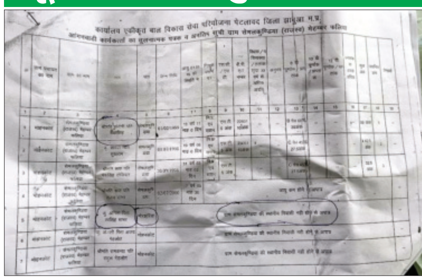

पेटलावद परियोजना अधिकारी द्वारा जारी सूची जिसमे संतोषी का चयन हुआ और अनिता को अपात्र घोषित किया गया था ।

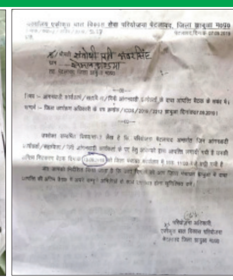

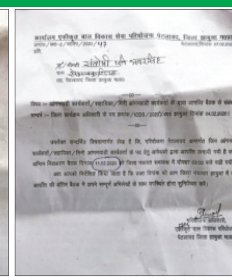

संतोषी को दस्तावेजो के साथ बुलाने के लिए भेजे गए सक्षम अधिकारी के नोटीस की कॉपी ।

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

15 महीने की कांग्रेस सरकार में निकली आंगनवाड़ी की भर्ती में फर्जी नियुक्ति करने का मामला पेटलावद विकास खण्ड के महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में सामने आया है। भर्ती की फर्जी प्रक्रिया कांग्रेस शासन में पूरी हुई और आदेश सत्ता में लोटी भाजपा सरकार के अधिकारियों ने जारी किया। मामला महिला बाल विकास विभाग का है जहां वर्ष 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए वेकेंसी निकली गई। जिसमें ग्राम पंचायत मोहनकोट के सेमलकुण्डिया के मेम्मर फलिये के लिए निकली पोस्ट के लिए कुल सात महिलाओं ने आवेदन किया। जिसमें से 04 महिला सेमलकुण्डिया फलिये की, 02 मोहनकोट और एक मोरझारिया फलिये की महिलाओं ने आवेदन किया। जिसमें से महिला बाल विकास द्वारा चस्पा सूची में 03 आवेदनकर्ता को अपात्र घोषित किया गया और सेमलकुण्डिया के मेम्मर फलिये की निवासी संतोषी पति भवरसिंह मुनिया 50 अंक के साथ सूची में श्रेष्ठ बताई गई।

सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वर्ष 2019 में विभाग द्वारा संतोषी को बुलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन होना बताकर आदेश आने पर ले जाने की बात कही गई। यहां तक मामला बिल्कुल सही-सही चला लेकिन विभाग द्वारा आवेदनों की जांच के बाद निरस्त किए गए आवेदनकर्ता अनिता पिता वरसिंह भाभर निवासी मोरझारिया द्वारा संतोषी मुनिया की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को जनसुनवाई के माध्यम से की गई। शिकायत दर्ज कर अपना पक्ष रखने के लिए संतोषी मुनिया को दिनांक 13.09.2019 और 11.02.2020 बुलाया गया। जिसमें जांच समिति के सामने उपस्थित होकर संतोषी ने अपने सम्पूर्ण दस्तावेज समिति के समक्ष पेश करते हुए आपत्तिकर्ता को पद हेतु अपात्र बताया गया। समस्त दस्तावेजों की जाँच के पश्चात समिति ने संतोषी को ही नियमानुसार पात्र पाते हुए उसे मौखिक रूप से कहा गया कि आपके पक्ष में निर्णय हुए है और आपका नियुक्ति आदेश आपको भेज देंगे। ऐसा कह कर रवाना कर दिया गया। नियुक्ति आदेश के इंतजार में संतोषी और उसके परिवार के पैरों तले जब जमीन खिसक गई। जब उसे पता चला कि प्रथम बार में पद के लिए अपात्र घोषित हुई अनिता पिता वरसिंह भाभर के नाम से आदेश जारी कर दिया गया। मामले में पेटलावद महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी मनासिया मेडम का कहना है कि हमारे द्वारा से संतोषी को ही पद के लिए सारे दस्तावेजों की जांच के बाद चयन किया गया था, लेकिन अपात्र अनिता की नियुक्ति जिले से कैसे हुई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूरे मामले में कैसे हुआ दस्तावेजों का हेर फेर और अपात्र अनिता की कैसे हुई नियुक्ति। किसके इशारे पर किया नियुक्ति आदेश प्रमाणित, दस्तावेजो के साथ पूरी खबर अगले अंक में करेंगे बड़ा खुलासा।

गृह मंत्रालय ने तय की कीमतें, 2400/- में होगी कोरोना की जांच

नईदिल्ली एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमतें तय कर दी हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 2400 रुपए लगेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझावों के बाद यह फैसला लिया गया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के साथ हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम को कहा कि कमेटी के सुझावों के बाद दिल्ली में कोविड-19 जांच की कीमत 2,400 रुपए निर्धारित कर दी गई है। दिल्ली में आज से रैपिड एंटीजन मेथोडोलॉजी से कोरोना की जांच होगी। इसके लिए दिल्ली में 169 सेंटर बनाए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह के आदेश के अनुसार दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हेल्थ सर्वे की शुरुआत हो चुकी है।

रक्षा मंत्री के ट्वीट में चीन का नाम नहीं होने पर भड़के राहुल

नईदिल्ली एजेंसी। पूर्वी लद्दाख की गलवां घाटी में चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को इस घटना पर ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट में चीन का नाम होने पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे सोशल मीडिया मंच पर ही कई सवाल भी पूछे।

राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए पांच सवाल पूछते हुए लिखा कि यह बहुत ही दर्दभरा है। उन्होंने पूछा, 'आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर आपने भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? संवेदना जताने के लिए दो दिन क्यों लगे?'

इसके अलावा राहुल ने आगे पूछा, 'जब जवान शहीद हो रहे थे तब आप रैलियों को संबोधित क्यों कर रहे थे? क्यों खुद छिप गए और क्रोनी मीडिया को सेना पर सवाल उठाने दिया?' अपने आखिरी सवाल में उन्होंने पूछा, 'आखिर क्यों बिकाऊ मीडिया को भारतीय सरकार के बजाय सेना पर दोष मढ़ने दिया गया?'

पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर अहम बैठक

नईदिल्ली एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक की शुरुआत में उन्होंने भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।

बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। पीएमओ ने जानकारी दी कि बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और अपने राज्यों की जमीनी स्थिति से उन्हें वाकिफ कराया। इन्होंने राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना और मजबूत किए जाने पर जोर दिया।

बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है, लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। हमारे जवान मारते-मारते मरे हैं।'

एक्टिव केस से ज्यादा संख्या इस महामारी से उबर चुके लोगों की

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में कोरोना के एक्टिव केस से ज्यादा इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'भारत में आज भी कुछ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर और आईसीयू की आवश्यक्ता पड़ रही है। समय पर जरूरी कदम उठाए गए, इसलिए आज हम इस महामारी के खिलाफ लड़ने और इसके संक्रमण के विस्तार को नियंत्रण करने में सक्षम हो सके हैं।'

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा, 'जैसे-जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्वास्थ्य संसाधनों का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे हम सभी कोरोना मरीजों का उचित इलाज कर पाएंगे। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर जोर देना होगा, जिससे कि हम टेस्ट कर सकें, मरीजों का पता लगा सकें और संक्रमित मरीजों को पृथक कर सकें।' उन्होंने कहा, तीन महीने पहले पूरी दुनिया पीपीई किट की कमी से जूझ रही थी। भारते का पास भी काफी कम किट थे। हम पूरी तरह बाहर से आयात करने पर निर्भर थे। लेकिन आज राज्यों को एक करोड़ से अधिक पीपीई किट और उतने ही छ95 मास्क दिए जा चुके हैं।

कंटेंमेंट एरिया में तील का ताड़ और राई का पहाड़

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

कहते है, किसी पर आई मुसिबत का अंदाजा तभी इंसान को होता है जब मुसिबत खुद उसके गले आकर पड़ती है। ऐसे ही कुछ हालात इन दिनों शहर में सुभाष मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहे है। पिछले दिनों सुभाष मार्ग के एक व्यक्ति को किसी गंभीर बीमारी के चलते इंदौर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुभाष मार्ग को कंटेंमेंट एरिया घोषित कर पूरी तरह सील कर दिया था। एरिया सील होने के बाद सुभाष मार्ग के कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया और एसडीएम हाय -हाय के नारे भी लगाए। उस वक्त जो विरोध हो रहा था उसका मकसद आर्थिक स्वार्थ माना जा रहा था। इस संबंध में झाबुआ एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों पर प्रकरण दर्ज भी करवाया था। पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों के सेम्पल लिए गए जिसमें एक और पॉजिटि मरीज निकल कर आया। जिसके बाद कंटेंमेंट एरिया में प्रशासन ने और अधिक सख्ती कर दी।

विरोध करने वालों का जो वक्तव्य सामने आया उसमें उन्होने कहा कि हमने विरोध सिर्फ आपातकाल रास्ता रखने के लिए किया था। इसके विपरीत चौराहों की चर्चाओं और सोशल मीडिया ने इसे सीजन के चलते धंधे में हो रहे नुकसान का विरोध बताया। हांलाकि हुए विरोध पर प्रशासन ने अपनी ऊंगली टेढ़ी करते हुए कार्रवाई भी कर दी। विरोधियों ने इसे द्वेष्तापूर्ण कार्रवाई बताया। कंटेंमेंट एरिया के लोगों का इस तरह का रवैया कि मानों उन्हे चारों और से दीवार में चुनवा दिया गया है या शीशा पिघलाकर इतनी मजबूत दीवार बना दी गई हो कि वह टूट ही न सके, क्षेत्र के व्यापारियों की मानसिकता व आर्थिक लोलूपता को दर्शाता है। पुलिस और प्रशासन द्वारा जो बेरीकेटिंग की गई है वह आसानी से हटाई जा सकती है। इसलिए आपातकाल के लिए रास्ता मांगना कतई उचित तो नहीं है। इससे पहले भी शहर में कई क्षेत्रों को कंटेंमेंट एरिया बनाया गया। वहां भी यही सख्ती प्रशासन ने दिखाई तो फिर सुभाष मार्ग को छूट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि नियम तो सभी के लिए एक से ही है। सुभाष मार्ग में लोगों का विरोध देखते हुए पिछले दिनों शहर में बने अन्य कंटेंमेंट एरिया के लोगों ने सोशल मीडिया पर जो टिप्पणीयां दी वह भी चिढ़ाने वाली ही थी। इसलिए कंटेंमेंट एरिया के लोगों को संयम रखते हुए तील ताड़ और राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए।

इस पूरे मामले में कंटेंमेंट एरिया में एक क्लिनिक संचालक दो डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को एसडीएम ने नियमों की उल्लंघन पर करना बताया। नियमों का उल्लंघन कितना व कैसा था यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिले के कई प्रायवेट व निजी क्लिनिक व चिकित्सक आए दिन किसी न किसी गड़बड़ को लेकर अखबारों की सुर्खियों में बने रहते है। कंटेंमेंट एरिया में जिन चिकित्सकों पर कार्रवाई हुई उनके पक्ष में मंगलवार को समस्त निजी चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ते हुए विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर व भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा और निजी चिकित्सकों पर की गई कार्रवाई को द्वेष्तापूर्ण बताया। जिन चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई उन पर सुभाष मार्ग में मिले कोविड के पहले मरीज के इलाज के आरोप है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति क्लिनिक पर मुंह के छालों का इलाज करवाने आया था। जब वह क्लिनिक पर आया था तब उसमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। अब प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में कितनी सत्यता है यह तो वो ही जाने। मगर चिकित्सकों द्वारा बताई गई बात के विपरीत स्थिति है तो प्रशासन का डंडा चलना वाजिब और सही है।

चिकित्सकों पर हुई कार्रवाई के बाद इस तरह से निजी चिकित्सकों का इकट्ठा होकर विरोध करना भी संदेह को जन्म देता है। वो कहते है ना कि झूठ बोलो तो इतनी जोर से बोलो कि लोग झूठ को सच मान ले। कंटेंमेंट एरिया में कैद दो चिकित्सकों ने फोन के जरिए अपने संघ को विरोध प्रदर्शन के लिए एकदम से एक्टिव कर दिया। निजी चिकित्सकों के संघ ने हुई कार्रवाई को धमकी देते हुए वापस करने की बात लिखित ज्ञापन में कही। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है तो निजी चिकित्सा संघ काम करना बंद कर देगा।

अब सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाना कहां तक उचित है। वहीं बकोल एसडीएम अभयसिंह खराड़ी यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशन में की गई। मतलब साफ की कार्रवाई से पीछे तो प्रशासन हटने वाला नहीं है। तो अब निजी चिकित्सा संघ को काम करना बंद कर देना चाहिए। और यूं भी पढ़े -लिखे और चिकित्सक होने के नाते विरोध प्रदर्शन, रैली, हंगामा यह कार्य शोभा नहीं देता। पूरे घटना क्रम में जिन 9 लोगों पर एफआईआर हुई थी उनमें कुछ अधिवक्ताओं के नाम भी है। बस फिर क्या था वकीलों ने भी अपना मोर्चा खोला और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ पहुंच गए ज्ञापन देने।

अब सवाल यह उठता है कि इतने पढ़े-लिखे, चिकित्सक, कानूनी जानकार अधिवक्ता इकट्ठा होकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रहे है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वह अभी कंटेंमेंट एरिया में ही है और जिन लोगों का कंटेंमेंट एरिया से कोई लेना-देना नहीं है व लोग प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे है, अब इसे क्या कहा जाए? हालांकि चौराहों पर चर्चा तो यह भी है कि कंटेंमेंट एरिया मतलब तिल का ताड़ और राई का पहाड़ या खिसियानी बिल्ली खंबा नौच रही है।

आशीष मूथा महाविद्यालय के विधायक प्रतिनिधि नियुक्त

माही की गूंज, पेटलावद। विधायक वालसिंग मेड़ा द्वारा विधानसभा क्षेत्र पेटलावद अंतर्गत संचालित शासकीय महावीर महाविद्यालय पेटलावद में विधायक प्रतिनिधि के रूप में आशीष मुथा को नियुक्त किया गया है। उक्त नियुक्ति पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्रपालसिंह, विधायक प्रतिनिधि जीवन ठाकुर, मन्नालाल हामड, प्रभात श्रीवास्तव, विक्रम चावड़ा, जावेद लोधी, बबलू राठौड़, नाना गोयल, समर मकवाना, राजकुमार मूथा, जगदीश जानी, मीडिया प्रभारी चंदू राठौड़ सहित उनके मित्रो तथा परिजनों द्वारा बधाई प्रेषित की है।

अनिल सेम्युअल जिलाध्यक्ष नियुक्त

माही की गूंज, पेटलावद। प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार-प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेष आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री शाशक चोपड़ा की स्वीकृति, मदन मोहन श्रीवास्तव प्रदेशाध्यक्ष और संतोष सोलंकी प्रदेश महामंत्री की अनुशंसा पर अनिल सेम्युअल की झाबुआ जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार-प्रसार अभियान के तहत पूरे प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाना है। जिले की जिम्मेदारी अनिल सेम्युअल की नियुक्ति से उनके सहयोगियों ओर साथियों ने उनको बधाई दी हैं। अनिल सेम्युअल से बताया कि जल्द ही जिले के समस्त विकास खण्डों में कार्यकरणी का विस्तार कर कार्य शुरू किया जाएगा।

आवास सहायता योजना की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी करें आवेदन

माही की गूंज, खरगोन। महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्हें आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त होता है, वे ऑनलाईन आवेदन कर 25 जून तक महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा कर सकते है। शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय खरगोन के प्राचार्य आरएस देवड़ा ने बताया कि सत्र 2019-20 के नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें आवास सहायता योजना की पात्रता है और जिन्होंने अभी तक ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है। वे ऑलाईन आवेदन कर 25 जून तक महाविद्यालय में हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

सांसद के गृहग्राम में ये कैसी कार्यवाही

शासकीय भूमि में सरकारी खर्चे से बने पुल से एसडीएम ने बंद की आवाजाही

किसानों को खेत में पहुंचने में हो रही परेशानी, बारिश होने के बाद खेत पर जाना होगा मुश्किल

इस पुलिया से एसडीएम ने किया आवागमन बंद।

इस तरह पुलिया के दोनों ओर खोद दी नाली।

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विधानसभा के रामा ब्लॉक के उमरकोट गाँव में एक अलग ही कानून चल रहा है। पिछले दिनों में यहां के बाशिंदों को कोरोना संकट के अलावा भी प्रशासन के कानूनी डंडे का सामना करना पड़ रहा है। यहां एसडीएम अभयसिंह खराड़ी का अमानवीय चेहरा लॉकडाउन में अतिक्रमण मुहिम में देखने मिल चुका है। जहां लॉकडाउन में तीन माह से बेरोजगार बैठे लोगों से रोजगार की अंतिम आस उनकी गुमटियां और दूकान उखाड़ फेक कर भूखे मरने को छोड़ दिया था। मामला सामने आने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार और उनके नेताओं की भारी किरकिरी हुई जो एक ओर कोरोना में गरीबो की सहायता करने की बात कर रही हैं और दूसरी ओर लोगों से अतिक्रमण के नाम पर सड़क पर फैंक कर बेरोजगार कर रही हैं। उमरकोट में चल रहे प्रशासन के डंडे के कहर के एक मामला सामने आया। जिसमें कई किसानों को प्रशासन की हठधर्मिता के कारण अपने खेतों पर पहुंचने के लिए भरी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी कार्यवाही पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे है क्योंकि उमरकोट सांसद गुमानसिंह का गृह ग्राम है और किसानों की परेशानी को देखते हुए उनके हस्तक्षेप से मामले को निपटाया जा सकता था लेकिन उसके उलट कार्यवाही के पीछे लोग सांसद की ही भूमिका बता रहे हैं।

सरकारी खर्चे से बने पुलिये से आवाजाही की बन्द

उमरकोट में शमशान भूमि से होकर अपने खेत पर जाने के लिए गांव के लगभग 20 से 25 किसानों को नाले पर से निकलने के लिए परेशान किसानों के लिए शासन ने 05 लाख की लागत से ग्राम पंचायत के माध्यम से समस्त शासकीय प्रक्रिया के साथ पुलिये का निर्माण किया गया और किसानों ने अपने खर्चे से उबड़-खाबड़ काली मिट्टी की दलदल वाली भूमि से निकलने वाले रास्ते पर मोर्हरम डाल कर आने-जाने का सुरक्षित रास्ता बनाया, लेकिन गांव के ही शंकर चौधरी द्वारा स्वयं के परिवार का शमशान भूमि पर अतिक्रमण होना बता कर शिकायत कर दी गई। जिसके बाद मौके पर रामा के तहसीलदार प्रवीण अहोरिया अपनी राजस्व टीम गिरदावर और पटवारी के साथ तीन बार दौरा किया। जिसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना बताकर किसी के आना- जाना नहीं रोकने की बात बोलकर किसानों को रास्ते से आने-जाने की मौखिक अनुमति दी गई। जो एसडीएम खराड़ी को नागावर गुजरी और चौथी बार खुद मौके पर पहुंच कर पुलिये के आसपास का रोड जेसीबी से खुदवा कर रास्ता बंद कर गए। किसानों की लाख प्रार्थना और कोशिशों के बाद भी एसडीएम ने किसानों की एक नहीं सुनी और खेत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया।

किसान हो रहे परेशान, बारिश में रास्ता हो जाएगा बन्द

आफ दी रेकॉर्ड शासकीय भूमि पर बने रास्ते के बन्द होने से अपने खेत पर पहुंचने के लिए 20 से 25 किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होते ही खेतों में बुवाई का समय शुरू हो चुका है और किसानों ने जैसे-तैसे मार्ग बदलकर अपने खेतों में बुवाई तो कर दी, लेकिन बारिश अधिक होने की दशा में मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। खेतो तक पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ऐसे में पुलिये से निकलना ही अंतिम रास्ता होगा। किंतु पुलिये के दोनों ओर एसडीएम खराड़ी द्वारा की गई खुदाई से आना-जाना सम्भव नहीं होगा। उमरकोट के परेशान किसान धन्ना, कान्हा, आनंदीलाल, राजराम और लीलाबाई ने बताया कि मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है और शासकीय भूमि से ही रोड निकल रहा है। पुलिया बना हुआ है। शिकायतकर्ता शंकर चौधरी की किसी प्रकार की कोई निजी भूमि भी नहीं है। अब रास्ता बंद होने से हमको परेशान होना पड़ रहा है। गांव के उमरकोट दरबार चित्ररंजनसिंह राजपूत का आरोप है कि रास्ते पर जो शमशान की भूमि हैं वो शासकीय है और गांव में हर समाज का अलग-अलग और एक सार्वजनिक शमशान अलग से बना हुआ हुआ हैं। मार्ग के पास दिख रही क्षत्रियां भी रावले राजवाड़े की है। ऐसे में प्रशासन की ओर से आए एसडीएम खराड़ी ने जानबूझ कर किसानों को परेशान करने के लिए अपने आका के इशारों पर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की है।

शिकायतकर्ता सांसद डामोर का खास

बताया जा रहा रहा शिकायतकर्ता शंकर चौधरी सांसद गुमानसिंह डामोर का खास है और किसानों का आरोप हैं कि कहीं न कहीं पूरी कार्यवाही और किसानों को परेशान करने के पीछे सांसद का हाथ है। भाजपा के लिए कई सालों तक किसानों की लड़ाई लड़ने वाले भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय बहादुरसिंह उमरकोट का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ओर अपने आपको किसान बेटा बता कर किसान हितेषी बताते हैं। और दूसरी ओर उनके नेता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर किसानों को ही परेशान करते हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले की पूरी जांच करवाने की मांग करते हुए रास्ते को शुरू किए जाने की मांग की है।

बावन जिनालय में श्री राजेन्द्रसुरिश्वरजी मसा का क्रियोन्धार दिवस तप जप के साथ मनाया

माही की गूंज, झाबुआ। श्रीसंघ के अध्यक्ष सुश्राावक संजय मेहता ने बताया कि स्थानीय श्री ऋषभदेव बावन जिनालय में बाबा गुरूदेव मंगलवार को क्रियोन्धार दिवस तप जप तथा अष्टप्रकारी पुजन कर मनाया गया। दादा गुरूदेव की क्रियोन्धार दिवस पर बावन जिनालय स्थित गुरूदेव राजेन्द्रसुरिश्वरजी मासा की प्रतिमा पर अभिषेक किया। इसके बाद केसर पूजन कर आरती उतारी गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय जैनप महिला परिषद् द्वारा गुरूदेव की अष्टप्रकारी पूजन पढ़ाई गई। पूजन का लाभ शकुन्तला कांतिलाल रूनवाल ने लिया। साथ ही गुरूदेव के जाप भी किए गए। दोपहर को क्रियोन्धार दिवस के उपलक्ष में कई तपस्वीयों ने आयम्बिल तप किया। आयम्बिल तप का लाभ मांगुबेन सकलेचा परिवार द्वारा लिया गया। शाम को दादा गुरूदेव की भक्ति करने के बाद आरती उतारी गई।

क्रियोन्धार दिवस क्यों मनाया जाता है

दादा गुरूदेव ने अषाढ़वती दसम के दिन संवत् 1924 को जावरा नगर मे उत्कृष्ट साधवाचार का पालन करने हेतु साधु समाज मे शिथिलता का त्याग कर उत्कृष्ट साधु जीवन अंगीकार किया था। उक्त जानकारी रिंकू रूनवाल द्वारा दी गई।

साध्वीश्रीजी मसा संयम जीवन के 35 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावक-श्राविकाओं ने की अनुमोदना

माही की गूंज, झाबुआ। पुण्यसम्राट गुरुदेव श्रीमद् विजय जयंतसेन सूरिश्वरजी महाराजा के द्वय पट्टधर गच्छाधिपति श्रीमद् विजय नित्यसेन सूरिश्वरजी मसा व आचार्य श्रीमद् विजय जयरत्नसुरीजी मसा की आज्ञानुवर्ती साध्वीश्री विद्वदगुणाश्री जी मसा को संयम जीवन के 35 वर्ष पूर्ण आज पूर्ण कर 36 वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर झाबुआ श्रीसंघ ने अनुमोदना की। श्रीसंघ के अध्यक्ष संजय मेहता सचिव मुकेश नाकोड़ा ने कहा कि हमारे लिए सौभग्य की बात है कि पूज्य साध्वीश्री का चातुर्मास झाबुआ में है। इस समय गौड़ी पार्श्व नाथ मंदिर में विराजित है।

मंगलवार श्रीसंघ के कई सदस्य गौड़ीजी पूज्य साध्वी श्री को 36 वें संयम दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने पहुंचे। इस अवसर पर सध्विश्री विद्वत गुणाश्री जी ने घर में रहकर सामयिक और धर्म क्रिया करें। साध्वी श्री ने कहा कि आचार्य श्री द्वारा जारी चातुर्मास के दिशा निर्देश का कोरोना महामारी के कारण सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त जानकारी अनिल रूनवाल द्वारा दी गई।

भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने शुरू हुआ संपर्क अभियान

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल उपलब्धियों से भरा रहा है, उपलब्धियां भी ऐसी हैं कि जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, राम मंदिर का निर्माण हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, धारा 370 की समाप्ति हो, तीन तलाक विरोधी कानून हो, ये सभी ऐसे काम हैं, जिनके बारे में लोग ये कहने लगे थे कि ये काम कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन मोदी सरकार ने देश की जनता से किए वादों को पूरा किया और असंभव लगने वाले इन निर्णयों को संभव कर दिखाया। उक्त बात भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक ने सोमवार को झाबुआ नगर में घर-घर संपर्क अभियान की शुरुआत के अवसर पर कार्यकर्ताओं को कही।

जिलाध्यक्ष नायक ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में शिवराजसिंह चौहान की सरकारें लगातार विकास और प्रगति के नए आयम स्थापित कर रही हैं। कार्यकर्ता मोदी सरकार की विगत 6 वर्षो की ऐतिहासिक उपलब्धियों व जन-कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक बनें, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक बूथ के 100 घरों तक 2 कार्यकर्ता पहुंचें और मोदी सरकार की योजनाओं पर केंद्रित पत्रक और प्रधानमंत्री का जनता के नाम पत्र देकर संपर्क करें। नायक ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यो का बताने के लिए जन-जन तक उनकी उपलब्धियां पहुंचे इसके लिए यह सघन अभियान चलाया है। जिसमें मोदी सरकार द्वारा देशहित के लिए जो भी फैसले लिए गए वो हर एक नागरिक के हित के लिए गए।

इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष बबलू सकलेचा ने कहा कि मोदी सरकार ना सिर्फ आम जनता को उनके हक के लिए उन्हे योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके इसलिए दिन रात कार्य कर रही है। वही गरीब जनता को ऐसे समय में जिस समय कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला हुआ है। ऐसे में उनकी हर संभव मदद कर रही है। वहीं गरीब आदिवासी किसानों के खाते में पैसा भी जमा किया जा रहा है। जिससे उन्हे थोड़ी राहत मिल सके। प्रधानमत्री मोदी के कार्यकाल मे अनेक बड़े-बड़े निर्णयों का फैसला लिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सकलेचा द्वारा बताया गया कि नगर के प्रत्येक वार्डों में घर-घर तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ और उनके द्वारा की गई उपलब्धियों को बताने का कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने मजबूत कंधों पर लिया है। जिसमें हर एक व्यक्ति को भाजपा सरकार द्वारा बनी योजनाओं का लाभ भी मिल सके और उसका बेहतर भविष्य बन सके।

कांग्रेस ने लगाया सरकार पर जनता के साथ कुठाराघात का आरोप

माही की गूंज, झाबुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करना जनता के साथ कुठाराघात है। कॅरोना महामारी से आर्थिक तंगी, बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई की मार से पहले ही आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आम जनता पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। भूरिया ने आगे कहा कि तेल की कीमतों में से वृद्धि में आम जनता की कमर तोड़ दी है। पूर्व में कच्चा तेल 66 रूपये प्रति बैरल था तो सरकार ने 16 रूपये टैक्स बढ़ा दिया। पिछ्ले 6 माह से क्रूड आयल की कीमत आधी रह गई है लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है जो कि देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश, प्रदेश में कोरोना के प्रकोप तथा लगातार लॉकडाउन के चलते चारों और बेकारी आर्थिक तंगी व महँगाई का तांडव हो रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई का और बोझ बढ़ा रही रही है। उक्त आरोप विधायक कांतिलाल भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, विधायक प्रतिनिधि तथा युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर पेट्रोल डीजल के दामों में रोज-रोज की जारी वृद्धि की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर मोदी सरकार आम जनता का गला घोट रही है। जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही

माही की गूंज, पेटलावद। कलेक्टर प्रबल सिपाहा के दिशा-निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी जीएस रावत के निर्देशन में मंगलवार को आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम ठिकरिया बरवेट तिराहा पर आरोपी दीपक अशोक कटारिया उम्र 22 वर्ष निवासी रामगढ़ द्वारा मोटर साईकल हीरो एचएफ डीलक्स एमपी 45 एमएल 9693 से अवैध शराब परिवहन की जा रही थी। जिससे चार पेटी मसाला मदिरा तथा वाहन जप्त कर मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शराब तथा वाहन की अनुमानित किमत क्रमशः 32 हजार रूपए तथा 40 हजार रूपए हैं। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई कार्यवाही में मुख्य आरक्षक कुसुम डामोर तथा आरक्षक डावर का योगदान रहा।

रावटी शादी समारोह में आए व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हरकत में आया रतलाम जिला प्रशासन

पेटलावद सहित कई गाँवों से गए थे मेहमान, लोगों में चर्चा का विषय

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद तहसील से लगे रतलाम जिले के रावटी गांव में पिछले दिनों हुए एक शादी समारोह में आए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद रावटी में हड़कम्प की स्थिति निर्मित हो गई। प्रशासन द्वारा रावटी शादी में आए लोगों की जांच और होम कोरोंटिन करने का काम शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादी में खाना बनाने आए किसी युवक को कोरोना निकला है। बताया जा रहा है युवक ट्रेवल हिस्ट्री में शादी में खाना बनाने जाने की बात सामने आई। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। चूंकि शादी जैन समाज में थी और रावटी के परिवार के काफी सारे रिश्तेदार बामनिया, पेटलावद, सारंगी, करवड़ भी रहते हैं और बताया जा रहा है इस शादी में कुछ लोग यहाँ से नहीं शामिल हुए थे लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा हैं। रावटी मामले को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है और विवाह समारोह में गए लोगों से चर्चा कर उनको होम कोरिनटिन होने और सामने आकर जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, न कोई आगे आकर अपनी जांच करवा रहा है। जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी मिली हैं कि शादी में फोटोग्राफी करने वाले युवक को भी रावटी प्रशासन द्वारा बुलाकर शादी में आऐ लोगो के फोटोग्राफ लेकर उनकी पहचान की जा रही हैं।

कोरीनटिन के लिए पहुँचे प्रशासन पर लगाए दुकानदारों ने गम्भीर आरोप

मामले के सामने आने के बाद रावटी प्रशासन शादी में शामिल लोगों की सूची हाथ में लेकर शादी में शामिल लोगों को कोरोइंटिन करने पहुँच गए। जिसका लोगों ने विरोध किया। इसमें से कई लोग खाद-बीज के व्यापारी है। जिन्होंने लाखों का माल भर रखा है। शोसल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो में साफ देखा गया कि प्रशासन पर व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए शादी में प्रशासन के लोगों के शामिल होने और सुरक्षा व्यवस्था में चूक करने के आरोप लगाए हैं। बरहाल मामले में रावटी प्रशासन बैकफुट पर नजर आया। वहीं शादी में शामिल झाबुआ जिले के लोगों को लेकर प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं है।

कोरेंटीन करने पहुंचे प्रशासनिक अमले से बहस करता व्यापारी।

स्व. इंदुमणी पंवार की स्मृति में परिजनो ने किया पौधारोपण

माही की गूंज, झाबुआ। पर्यावरण सुरंक्षा एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिये पौधारोपण कर नगर को सदेंश दिया। झाबुआ के तात्कालीन एसपी महेशचन्द्र जैन द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए दो नारे दिय थे जिसमें परिवार में किसी का जन्मदिन हो या फिर मरने पर परिवार के सदस्य या फिर अन्य की स्मृति में एक पैड अवश्य लगाये। इसी संदेश को यादगार बनाते हुये हाउसिंग बोर्ड कालोनी मे स्वर्गीय इंदुमणी पंवार की स्मृति मे उनके परिजनो ने पौधारोपण किया। इस दौरानप पारिवारिक सदस्य के रूप मे विजय सिंह पवार, कुलदीप पंवार,कार्तिक पवार, नरेन्द्र पवार, विशाखा पवार, कृतिका पवार , कैलाश सिंह बघेल, देवेन्द्र सिंह , ज्योति चौहान, राजकुमारी चौहान, लता चौहान, रेखा बघेल, लक्ष्यसिह चौहान, ध्र्रुवसिह चौहान, सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि विगत 2 जून को इंदुममणी पवार का आकस्मिक निधन हो गया था। जिसमे उनकी स्मृति मे मगलवार को हाउसिंग बोर्ड कालोनी मे परिजनो ने पौधारोपण कर हरियाली को बढावा व पर्यावरण को स्वच्छ एव सहजने के लिए संदेश दिया।

अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले एक बार फिर हुए बुलंद

जिला प्रशासन की कार्यवाही नहीं होने पर बढ़ा अवैध कब्जा

माही की गूंज, झाबुआ।

लॉकडाउन से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुहिम कर अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्यवाही कर उन्हे हटाया गया था, लेकिन जहां एक ओर कोरोना वायरस ने झाबुआ जिले में ज्यो ही दस्तक दी। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण की ओर से पुरा ध्यान ही हट गया है। नगर में आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा शासकीय जमीनों पर कब्जा कर तम्बु तान दिए गए है और सुबह-शाम बैठकर वहां चौकीदारी करते रहते है। यही नहीं उनका मानना है कि एक दो साल तक अगर जमीन पर कब्जा कर लिया गया तो शासन द्वारा जमीन का पट्टा मिल जाएगा और जमीन अपने नाम हो जाएगी। इस फिराक में ना जाने कितने लोगों ने शासकीय जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अधिग्रहण कर रखी है। वहीं जिला प्रशासन जहां वर्तमान में कोरोना संक्रमण महामारी की ओर पूरे जिले को बचाने में लगी हुई है। वहीं इन अतिक्रमणकर्ताओं का थोड़ी सहुलियत मिल रही है कि इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर सहित जिले भर में अतिक्रमणकर्ताओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पूर्व में एसडीएम डॉ. अभयसिह खराड़ी के द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं पर मुहिम चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था। जिस पर से कई ऐसे अतिक्रमणकर्ता भी थे जिन्होने इस कार्यवाही को देखकर ही अपने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जहां इस ओर थोड़ी ढील दी गई, वहीं अतिक्रमणकर्ताओं ने फिर से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिन्हे अभी कोई डर नहीं है। क्योंकि उन्हे मालूम है कि जिला प्रशासन अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के संकट से जिले को बचाने मे लगा हुआ है। जिस पर से हमारी ओर कोई ध्यान नहीं जाएगा। नगर में कई जगह जिनमें लक्ष्मीनगर के पास, गौ शाला के पास वाले खुले क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जिस पर जिला प्रशासन की कोई नजर नहीं पड़ी है। ऐसे में जिला प्रशासन को एक बार और पूर्व की तरह अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही को शुरू करना पड़ेगा। जिससे की अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके।

माइक्रो फायनेंस कंपनियां लोन की किश्त के लिए बना रही दबाव

समूह लोन में मेडिक्लेम बीमा होने पर महिला को नहीं मिला स्वास्थ्य लाभ

माही की गूंज, बामनिया।

कोरोना वायरस की रोकथाम की दिशा में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार ने आम लोगों को बैंकों के ऋण आदि जमा करने में रियायत के निर्देश जारी किए थे। किन्तु महिला समूहों को लोन देने वाली माइक्रो फायनेंस कम्पनियां ब्याज लगने की बात से भ्रमित कर किश्त भरने का दबाव बना रहे है। इस कम्पनी द्वारा समूह लोन के साथ ही जो बीमे किए जाते है। उसमें मेडिक्लेम बीमा भी सम्मिलित होता है। किन्तु ग्राम अमरगढ़ की एक अस्वस्थ्य ग्रामीण महिला को उपचार होने तक बीमा राशि दिए जाने की बात कहते रहने वाली कम्पनी ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हुई महिला को बाद में बीमा राशि देने से इंकार कर दिया। ग्रामीण महिला के परिजनों को येन-केन उपचार की बड़ी राशि की व्यवस्था कर महिला का उपचार करवाना पड़ा।

समीपस्थ ग्राम अमरगढ़ की महिला कंकूबाई भूरिया द्वारा क्षेत्र की स्वतंत्र माइक्रो फायनेंस कम्पनी के माध्यम से समूह लोन लिया था। जिसमें नियमानुसार होने वाले चार प्रकार के बीमों की राशि भी जमा की गई थी। जिसमें स्वंय तथा परिवार के सदस्य का अस्पताल में उपचार होने पर निर्धारित बीमा राशि कम्पनी की ओर से दी जाना थी। किन्तु कंकूबाई भूरिया का आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने पर पेटलावद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जिस पर कम्पनी वालों ने उन्हें मेडिक्लेम बीमा राशि का लाभ पाने के लिए रतलाम के एक अस्पताल में उपचार करवाने को कहा। जहां पर कंकूबाई को भर्ती किए जाने के बाद माइक्रो फायनेंस कम्पनी ने किसी भी प्रकार की बीमा राशि का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कह दिया। गरीब ग्रामीण महिला के परिजनों ने जैसे-तैसे राशि इकट्ठा कर स्वयं के खर्च से इलाज करवाया और अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाए।

कम्पनियां करती है ग्रामीणों को भ्रमित

लोन देने का लालच देकर माइक्रो फायनेंस कम्पनियां ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले लोगों को शुरूआत में कई तरह से भ्रमित करती है और लोन से मिलने वाली कई सुविधाएं और लाभ बढ़-चढ़कर बताती है किन्तु असल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार लोन लेने के बाद ग्रामीण इनके चंगुल में फंस जाता है और ये लोन राशि कई गुना अधिक राशि गरीब ग्रामीण परिवार से हासिल करने में कामयाब हो जाते है। कोरोना रोकथाम में लागू लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा बैंकों और फायनेंस कम्पनियां आदि से अपने ग्राहकों से ईएमआई के लिए दवाब नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे । 30 जून तक की इस सुविधा को सरकार ने अब 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किन्तु उसके बावजूद माइक्रो फायनेंस कम्पनियां समूह लोन की किश्त के लिए रूबरू एवं फोन के माध्यम से आम ग्रामीणों को भ्रमित कर किश्त भरने का दवाब बना रहे है। इनके द्वारा ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि सरकार ने किश्त भरने से मना नहीं किया है और तुम लोग नहीं भरोगें तो तुम्हें ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार से भ्रमित कर येन-केन किश्त की राशि भरने का दवाब बनाते चले आ रहे है। लॉकडाउन में अपने आय के सारे स्त्रोत बंद होने के कारण जैसे-तैसे अपने परिवार का गुजारा करने वाले गरीब ग्रामीणों पर माइक्रो फायनेंस कम्पनियां दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रही है। मामले में कृष्णआर्य, स्वतंत्र माइक्रो फायनेंस कम्पनी का कहना है कि हमारे द्वारा किश्त भरने का दवाब नहीं बनाया जा रहा है। मेडिक्लेम बीमा अवधि पूरी हो जाने के कारण संबंधित महिला को नहीं मिल पाया है। वही विधायक वालसिंह मेड़ा ने कहा कि हमारी सरकार थी तो हमने किसानों का एक लाख तक का कर्जा माफ किया। शिवराजसिंह भी इन महिलाओं का समुह का लोन माफ करे। अभी अब हमारी सरकार ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं।

फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों के सामने पेट पालन का संकट

सीएम शिवराजसिंह चौहान ने लॉकडाउन काल का औसत मानदेय भी नहीं दिया

माही की गूंज, झाबुआ।

पूर्ववर्ती कमलनाथ शासन में कई उलझनों में उलझी सहायक प्राध्यापक भर्ती से नियुक्ति होने के कारण वर्षों से कार्य करने वाले अतिथि विद्वान दिसंबर 2019 से फॉलेन आउट हैं। कई जद्दोजहद के बाद भी मार्च माह से च्वाईस फिलिंग हो चुकी सूची तक जारी नहीं की गई हैं। जिससे इनके परिवार का पेट पालन का संकट गहराता जा रहा हैं। कांग्रेस शासनकाल से अटकी 450 पदो की स्वीकृति व नियमितीकरण फाईल पर भी कोई निर्णय नहीं लेने से कई लोग फांसी तक लगा चुकें है। फिर भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ हैं। जबकि धरना स्थल व सोशल मीडिया में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कमलनाथ सरकार को कोसते हुए कहा था कि, यह सरकार अंधी और बहरी हैं, इतने दिनों से यह सभी अपने हक और अधिकार मांग रहें हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हैं। यदि हमारी सरकार होती तो कब से सबको अंदर लेकर नियमित कर दिया होता।

परंतु देखने में आता हैं कि, बीजेपी ने भी केवल सत्ता पाने के लिए ही यह ढकोसला किया था। 3 माह सरकार बने हो गयें, पर केवल सीएम से लेकर मंत्री, विधायक आदि केवल समझाने में ही लगे हैं, वास्तविकता काफी दूर हैं। अब तक फॉलेन आउट को सीएम शिवराजसिंह चौहान ने प्रतिबन्ध काल का औसत मानदेय तक नहीं दिया हैं। अतिथि विद्वान मोर्चा के मीडिया प्रभारी शंकरलाल खरवाडिया का कहना हैं कि, हम हर तरह से टूट चुकें है, हमारें सामने रोजी-रोटी का संकट खडा हो गया हैं, सीएम और मंत्रियों के झूठे आश्वासनो से पेट नहीं भरता हैं, शिवराज सरकार शीघ्र हमारा विस्थापन करें, अन्यथा फिर से भोपाल के शाहजहांनी पार्क में आंदोलन का आगाज होगा।

जिला चिकित्सालय में लगा गंदगी का अंबार

वेस्ट मटेरियल का कचरा कई दिनों से नहीं हो रहा साफ, इन्दौर से नही आ रहा वाहन

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला चिकित्सालय में इन दिनो सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ही नही ध्यान दिया जा रहा है। जिसके कारण अपशिष्ट पदार्थो का अव्यवस्थित ही बाहर आना दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर जिला अस्पताल सफाई को लेकर बडे बडे ढिडोरे पिटाता हो लेकिन वास्तविकता में हकिकत की धरातल पर सफाई के नाम पर सिर्फ अंगुठा दिखाया जा रहा है। पूर्व में अस्पताल में अव्यवस्थाओ को लेकर भी समाचार पत्रो में प्रकाशन किया गया था। उसके बाद से वरिष्ठ अधिकारियो ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि जिला अस्पताल में सफाई को लेकर कोई भी लापरवाही नही बरती जायेगी लेकिन विगत कुछ दिनो बाद ही जिला अस्पताल में सफाई के नाम पर दाग लग गया।

जिला अस्पताल मे मुख्य गेट के पास ही बने कचरे के ढेर का एक कम्पाटमेन्ट बनाया गया है जिसमे अस्पताल के वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है। लेकिन कुछ दिनो से ये वेस्ट मटेरियल उस जगह से बाहर आने लगा है। वही जहां लोगो का आने जाने का रास्ता है ओर पास ही बने एसएनसीयू वार्ड मे नन्हे मुन्ने बच्चो का वार्ड होने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। यहि नही इससे पूर्व भी स्वास्थ्य संबधी कई ऐसी अव्यवस्थाये जिला अस्पताल में बिखरी पडी रहती है जिससे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड सकता है। कई बार इस अव्यवस्थाओ के बारे में उच्च अधिकारियो से संपर्क करना चाहा तो वे सिर्फ अपने आप को कोविड -19 में ही व्यस्त बताते हुये इस बारे मे कुछ भी सटिक जबाव नही दे पाये। जिससे यह जाहिर हुआ कि अपने कर्त्तव्यो से अधिकारी किस तरह मुंह मोडते है। जिला अस्पताल में इस तरह गंदगी का आलम होना क्या मरिजो के स्वास्थ्य पर असर नही डालेगा।क्या इससे अन्य बिमारियो से ग्रसित होने की कोई संभावना नही है। ऐसे कई सवाल है जो इस तरह की गंदगी होने पर जिला अस्पताल की ओर उठते है। लेकिन शायद विवादो के घेरे मे रहने की जिला अस्पताल को रहने की आदत सी हो गई है।

जिम्मेदारो का कहना-

इस वेस्ट मटेरियल के लिय इन्दौर से गाडी आती है। जिसमे पुरा मटेरियल गाडी में भरकर इन्दौर के लिये रवाना किया जाता है। अभी कुछ दिनो से यह वाहन नही आ पा रहा है। लेकिन यदि कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है तो मै इसे दिखवाता हूँ।

डॉ. बी.एस. बघेल.,सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, झाबुआ।

वेस्ट मटेरियल को अलग से इखट्टा किया जाता है।जिसे इन्दौर से गाडी लेने आती है। अभी मे कोविड-19 में जा रहा हू बाद मे बात करता हूँ।

डॉ. सावनसिह चौहान, आरएमओ, जिला चिकित्सालय, झाबुआ।

लॉकडाउन हो या फिर कर्फ्यू शराब कारोबारियों को नही पड़ता कोई असर

नगर सहित जिले भर के ढाबों पर होती रही है अवैध शराब की कालाबाजारी

माही की गूंज, झाबुआ।

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। जिस पर से पूरे जिले भर में लॉकडाउन कर आंशिक छूट देकर ही कार्य किए जा रहे थे। लेकिन इसके बीच पूरे लॉकडाउन में शराब माफियाओं ने जमकर कालाबाजारी कर अच्छा खासा पैसा वसुल लिया।

सुत्रों के अनुसार माने तो जहां एक ओर पूरे जिले भर में दूकानों को खोलने के आदेश नहीं दिए गए थे तब से लेकर अब तक शराब कारोबारियों द्वारा ने अपने माल की खपत कांउटर पर ना करके आसपास के छोटे-छोटे ढाबों वालों को पकड़कर उन्हे माल सप्लाय किया। जिस पर से उनके द्वारा पड़ा हुआ स्टॉक कम से कम खत्म हो सके। यही नहीं नगर में चल रहे ढाबों के साथ ही आसपास के क्षेत्रो में भी शराब की पेटियां भी उतारी जा रही है। यह सिलसिला आज तक चल रहा है। जहां एक ओर लॉकडाउन के तहत जिला प्रशासन की निर्धारित समय सीमा में छूट प्रदान की गई है। वहीं शराब माफियाओं को यह समय रास नहीं आ रहा है। शराब का कारोबार लॉकडाउन के पूर्व से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से शराब के कारोबार में वृद्धि भी जरूर हुई है । वहीं जहां शराब की किमतों में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन गुना महंगी शराब बिकने लगी थी। वहीं ढाबों पर शराबियों की भीड़ भी देखी जा सकती थी। जहां पुरे नगर सहित जिले को बंद कर रखा था वहीं दूसरी ओर ढाबे वाले अपने ढाबों पर शराबियों को बैठाकर शराब पिलाते थे। वहीं उनसे तीन गुना पैसा भी वसूला जाता था। शराब माफियाओं के द्वारा इन ढाबों को कहा जाए तो एक तरह से गोद ले रखा है जिससे उनकी भी गाड़ी चल रही है ओर ढाबे वालों को भी आसानी से शराब मिल जाती है। पूर्व में जहां जिले भर के साथ ही नगर में शाम 6 बजे तक के लिए ही आंशिक छूट प्रदान की गई थी जिस पर से शराब माफियाओं के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। लेकिन ढाबों पर यही शराब आसानी से तीन गुना किमत में उपलब्ध हो रही थी। इस पूरे मामले में एक बात समझने की है कि यदि लॉकडाउन पुरे जिले भर के साथ ही नगर की सभी दुकानों के लिए लागू हुआ था तो शराब के कारोबार करने वाले और ढाबों पर बैचने वालों पर यह नियम लागू क्यों नहीं हुआ यह सोचना का विषय है।

किसका संरक्षण है मिला

आखिर इन शराब माफियाओं के साथ ही इन ढाबों पर किसकी कृपा बरस रही है। लगता है कि कुछ ही लोगों पर जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के आदेश होते है। कुछ लोगों को इसकी छूट प्रदान की गई है। वहीं वर्तमान में जहा जिले भर के साथ ही नगर में दुकानों के खुले रहने का समय 8 बजे तक कर दिया है तो क्या ढाबे रात के 12 बजे तक चल रहे है। क्या आबकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर कौन है जो इन सबको संरक्षण दिए हुए है?

रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

माही की गूंज, खरगोन। मप्र परिमंडल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है। 7 जुलाई तक वेबसाईट पर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल की 1330 तथा ग्रामीण डाक सेवक सहायक शाखा डाकपाल की 1504 रिक्त पदों की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

बाजारो मे इन दिनो दिख रही सैकड़ो की तादात मे ग्रामीणो की भीड़

कृषि दुकानों पर सामान खरीदने आ रहे ग्रामीण, एक भी संक्रमित व्यक्ति कहीं कोरोना को ना दे दे दस्तक

माही की गूंज, झाबुआ।

लॉकडाउन के तहत आंशिक छूट मिलने के बाद से नगर में इन दिनों मिली ग्रामीण अंचलों से हजारों की तादात में भीड़ नगर में आती हुई दिखाई दे रही है। वही सोश्यल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों को ताक पर रख कर नगर में आवाजाही शुरू हो चुकी है। वहीं ना ही लोगों के द्वारा मुंह पर मास्क का उपयोग हो रहा है और ना ही सोश्यल डिस्टेसिंग का पालन। वहीं हजारों की तादात में ग्रामीणों का इस तरह से आना आने वाले समय में कही कोरोना संक्रमण को दावत ना दे दे।

पूर्व में भी जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि नगर में मिली आंशिक छूट का नगर वासी तथा ग्रामीणों के द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों की सैकड़ों की तादात में नगर में प्रवेश पूर्ण रूप से शुरू हो गया है। जहां एक ओर बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है उसके तहत बाजारों में कृषि, बरसाती तथा अन्य दुकानों पर ग्रामीणों की भीड़ देखी जा रही है। जिसमें दूकानदार केवल अपने साामन बेचने में लगा हुआ है। ग्रामीणों की ना तो सोश्यल डिस्टेसिंग रखी जा रही है और ना ही मुंह पर मास्क रखने को कहा जा रहा है। ऐसे में यदि वर्तमान में कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है तो वो ना जाने कितनों को संक्रमित कर देंगा। हाल फिलहाल में ही नगर के सुभाष मार्ग में रहने वाले युवक को कोरोना संक्रमण पॉजिटिव आया है। जिसका ईलाज इन्दौर चल रहा है। जिस पर से सुभाष मार्ग सहित अन्य मार्गो को भी कंटेन्टमेंन्ट एरिया घोषित कर उसे सील कर दिया गया है। अब युवक के परिजनों की रिपोर्ट आना शेष रह गई है। ऐसा ही कुछ बाजारों में फैली भीड़ के कारण कोई संक्रमित मरीज यदि एक भी पाया तो वो ना जाने कितनों को संक्रमित करेगा। जिला प्रशासन के निर्देशों में हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आम दिनों में बाजारों को

छूट देने पर हाट बाजार जैसा ही माहौल प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। जो कही ना कही कोरोना को फिर से झाबुआ जिले की ओर बुलाने की कोशीश कर रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की दरकार है।

एठलेन रोड में अधिग्रहण भूमि की क्षतिपूर्ति मुआवजा व पुर्नस्थापना की सरकार से की मांग

सांसद को दिया ज्ञापन

माही की गूंज, भामल। नारायण पालरा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे भारत माला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित होकर उक्त आठ लाइन रोड का कार्य प्रगति पर है। अभी भी उक्त मार्ग हेतु अधिग्रहण की गई आवासीय तथा कृषि भूमि के साथ आवासीय मकान व भूमि में स्थित वृक्ष के मुआवजे के लिए क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। जिन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे आदिवासियों को जमीन तथा मकान के पट्टे तक आवंटित नहीं किए गए। नतीजन वर्षो से रह रहे आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की गई। जिसमें शासन की योजनाओं के तहत ही कूप खनन व पाइप लाइन तक की गई लेकिन अब उसे सरकारी भूमि मानकर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिससे रोजी-रोटी के साथ बेघर हो रहे आदिवासी किसान परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व में 18 दिन तक थांदला एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन भी किया। जांचकर मुआवजा देने का आश्वासन भी मिला लेकिन न कोई जांच की गई न कोई मुआवजा आज तक दिया गया।

किसानों ने दावा-आपत्ति भी दर्ज की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसपर एक बार फिर जनजाति विकास मंच जिला झाबुआ की ओर से झाबुआ-रतलाम सांसद को सरकार से मांग करते हुए ज्ञापन दिया। जिसमें अपने आरोपों के साथ मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारी आज तक हमारे खेतों व घरों तक नहीं आए। ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए फसल नष्ट कर पाइप लाइन तोड़ रहे हैं व ठेकेदार दबंगता दिखाते हुए पुलिस व प्रशासन की धमकियां देकर जेल भिजवा देंगे की गर्वोक्ती भी कर रहे हैं। साथ ही मांग पत्र में कहा है कि परियोजना के विरोधी नहीं है, किंतु संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हम जनजाति किसान परिवारों के हक व अधिकार सुनिश्चित किए जाकर भूमि का बंदोबस्त, जमाबंदी कर भूमि के पट्टे अथवा मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाए। साथ ही अधिग्रहण पूर्ण स्थापना व मुआवजे का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई। सांसद गुमानसिंह ने मांग पत्र लेकर सरकार से आदिवासी किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए आश्वस्त किया।

मलेरिया प्रभावित ग्रामों में कीटनाशक छिड़काव प्रारंभ

माही की गूंज, झाबुआ। जिले में मलेरिया रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए 16 जून से चिन्हित 2 उप स्वा.केन्द्र के 2 ग्राम की 3445 जनसंख्या को कीटनाशक सिन्थेटिक पायरेथ्राईड 5 प्रतिशत के दो चक्र छिड़काव कर मलेरिया रोग से सरंक्षित किया जा रहा हैं। चयनित मलेरिया प्रभावित ग्रामों में प्रथम चक्र 16 जून से प्रारंभ किया जाकर 13 जुलाई तक तथा दूसरा चक्र 1 से 29 सितम्बर तक चलाया जाएगा। कीटनाशक छिड़काव प्रशिक्षित दल द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष जिले के कल्याणपुरा ब्लॉक के हाईरिस्क वाले क्षेत्रों में 1 एपीआई से अधिकता वाले क्षेत्रों के ग्रामों को कीटनाशक छिड़काव में शामिल किया गया हैं। घरों में शत प्रतिशत छिड़काव के लिए छिड़काव तिथियों की जानकारी संबधित ग्राम की बहु.स्वा.कार्यकर्ता एएनएम आशा, पंच, सरपंच, को छिड़काव के पूर्व दी गई हैं।

आम जनता को सलाह दी गई है कि कीटनाशक एसपी 5 प्रतिशत का असर ढ़ाई माह तक दिवारों पर रहता हैं ऐसे ग्राम जहां कीटनाशक का छिड़काव घरों के अन्दर किया गया है, उन घरों में रंग रोगन, लिपाई-पुताई कीटनाशक दिनांक से ढ़ाई माह तक नहीं की जाए। खाना बनाने वाले कमरे, सोने वाले कमरे तथा भंडार कक्ष, शौचालय तथा समस्त कमरों में छिड़काव अवश्य कराए। छिड़काव के दौरान खाने-पीने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखकर ढंक दिया जाए। छिड़काव दल के कार्य के अवलोकन, सुपरवीजन तथा समीक्षा के लिए स्थानीय क्षेत्रीय स्वा.कार्यकर्ताओं, सुपरवाईजर की ड्यूटी लगाई गई हैं। ग्राम की आशा कार्यकर्ता ग्राम में छिड़काव कार्य के दौरान छिड़काव दल के साथ में रहकर छिड़काव कार्य करवाएगी। छूटे तथा बन्द मकानों को कार्य समाप्ति पर पुनः सम्पर्क कर छिड़काव किए जाने के लिए छिड़काव दल को प्रशिक्षण में समझाईश दी गई हैं। आम जनता से अपील की गई है कि छिड़काव दल पहुंचने पर अपने घरों के समस्त कमरों में कीटनाशक का छिड़काव कराएं, ताकि घर के लोग मलेरिया रोग से सुरक्षित रहे तथा अपने क्षैत्र में मच्छर जनित रोग से होने वाले रोगों के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।

संपादकीय

कोरोनाः सावधानी ही बचाव का अंतिम रास्ता

कोरोना संक्रमण में भारत का दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचना जितना दुखद है, उससे कहीं अधिक चिंताजनक है। इस चिंता का इजहार जन-सामान्य से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक होना स्वाभाविक है। माना जा रहा था कि कोरोना भारत में ज्यादा नहीं फैलेगा और दुनिया को भारत से उम्मीदें भी हैं, लेकिन पिछले महीने भर में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, हमारी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अब भारत से आगे केवल तीन देश बचे हैं। रूस में पांच लाख से अधिक मामले हैं, ब्राजील में आठ लाख से ज्यादा और अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा। भारत में संक्रमण की यही रफ्तार रही, तो जुलाई में ही कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंच जाएगा। तेज बढ़ते संक्रमण से पता चलता है, लोग पूरी तरह सचेत नहीं हैं। कोरोना से रक्षा के दिशा-निर्देशों के प्रति लापरवाही ज्यादा दिख रही है, तो नतीजे सामने हैं। कुछ राज्य फिर लॉकडाउन के पक्ष में हैं। कोरोना प्रबंधन की ऐसी-ऐसी खामियां सामने आने लगी हैं, जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों और शवों के साथ हो रहे व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्थिति को विकट बताया है। खबरों का संज्ञान लेते हुए तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने अस्पतालों के हालात पर चार राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोरोना प्रबंधन की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तब जांच की संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में जांच का घट जाना अनुचित है। शीर्ष अदालत ने यह भी कह दिया कि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बिस्तर खाली होने के बावजूद मरीज भटक रहे हैं। कोर्ट को शव प्रबंधन पर भी चिंता जाहिर करनी पड़ी है, तो स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। जहां चेन्नई में सरकारी एजेंसियां मृतकों की अलग-अलग संख्या बता रही थीं, तो वहीं दिल्ली में भी यही शिकायत सामने आ गई। जब एजेंसियां मौत के आंकड़े ही दुरुस्त नहीं रख पा रही हैं, तो संक्रमितों की संख्या कितनी पुख्ता होगी, सोच लेना चाहिए।

देश में सबसे अधिक 94 हजार से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, उसमें भी मुंबई सबसे बुरे हाल में है। वहां की सरकार केंद्र से सहयोग मांगने को विवश हुई है। मुंबई के सिविक संचालित अस्पतालों में वार्ड-ब्वॉयज और नर्सों के 30 प्रतिशत स्टाफकी कमी है। विकसित शहर मुंबई में जब सेहत व्यवस्था चरमराने लगी है, जब राष्ट्रीय राजधानी कराहने लगी है, तब देश के दूसरे इलाकों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। बेशक, जब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, तो व्यवस्था की खामियां-कमियां खुलकर सामने आएंगी ही, लेकिन जरूरत इन खामियों को लेकर उदास होने की नहीं है। हर किसी को अपने स्तर पर सोचना होगा कि वह संक्रमण के पक्ष में है या विपक्ष में। हम अपनी उदासीनता या लापरवाही से ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि अस्पतालों पर ज्यादा बोझ पड़े? हिम्मत के साथ हमें मुकाबला करना है। तीन लाख की भयावह संख्या सताने लगे, तो यह भी सोचना चाहिए कि उसमें करीब डेढ़ लाख लोग कोरोना के खिलाफ विजयी रहे हैं। हम सोलह आना सावधान रहकर ही विजयी होंगे और हमारा देश भी।

राष्ट्रवादी वहीं जो समस्या नहीं, समाधान बताए

राष्ट्रवादी कौन है, कौन नहीं। कौन असली राष्ट्रवादी है और कौन नकली, भारत में राजनीतिक दल इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। गला काट बहस कर रहे हैं। कुछ लोग तो विदेश तक के स्वनामधन्य लोगों से इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं और अपना एकतरफा फैसला सुना देते हैं कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है लेकिन इसके लिए वे सभी भारतीयों को जिम्मेदार नहीं मानते। अंदरखाने मानते भी हों तो इस बाबत बोलने की हिम्मत नहीं रखते। इसके पीछे वोट की राजनीति भी एक बड़ा कारक हो सकती है। राजनीति में अर्धसत्य का बोला जाना कोई नई बात नहीं है।

अब यह अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दौर तो है नहीं कि अपने विरोधी का नाम लिए बगैर फूल-पत्तियों के जरिये भी बहुत कुछ कह दिया जाता था लेकिन अब तो एक-दूसरे को नाम लेकर भ्रष्ट-बेईमान कहा जा रहा है। लक्षणा-व्यंजना की जगह अभिधा ने ले लिया है। सेना तक से उसके अभियान के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। यह भी नहीं सोचा जाता कि सेना ने जिस अभियान को अंजाम दिया है, उसे अपनी जान पर खेलकर दिया है। राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों के स्तर पर ही ऐसा कुछ किया जाता है। वैसे भी विरोध शालीनता के दायरे में ही अच्छा लगता है। विरोध एक तरह की असहमति हो सकती है, विद्रोह कदापि नहीं। घर के मामले घर में ही सुलझाने की भारतीय परंपरा है।

पंचायत में तो दो पड़ोसियों के विवाद सुलझाए जाते हैं। आजकल चीन के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने हैं। विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। इस तरह के प्रसंग संवेदनशील होते हैं और जनता को कितनी बात बताई जानी चाहिए और कितनी नहीं, यह सरकार और सेना तय करती है। सीमा पर सैनिकों के बीच छिटपुट संघर्ष चलते रहते हैं, उसे बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकार की रणनीति क्या है? वह क्या कर रही है? उनका सवाल है कि क्या चीन ने भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया है तो इसका जवाब सरकार दे भी चुकी है कि चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वर्ष 1962 के बाद से जम्मू-कश्मीर में भारत की भूमि का लगभग 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूभाग चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 2 मार्च 1963 को चीन-पाकिस्तान श्सीमा समझौते श् के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को दे दिया था। जो राजनीतिक दल लंबे समय तक भारत के सत्ता केंद्र में रहा, उसने कभी सोचा भी नहीं कि चीन के कब्जे में जो भारतीय भूभाग चला गया है, उसे निकाला कैसे जाए? उस दल के नेताओं को इस बात की चिंता जरूर खाए जा रही है कि चीन ने हाल में लद्दाख की कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए मौजूदा सरकार क्या कर रही है?

सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने अगर यह कहा है कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सेना को पाकिस्तान और चीन से ही नहीं, अपने देश के आस्तीन के सांपों से भी चुनौती मिल रही है। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से सेना को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करनी पड़ रही है। आतंकवादियों का सामना करने वाली सेना पर पत्थरबाजी करने वाले लोग भी इसी देश के हैं। सेना हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देती है। जम्मू-कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो सेना ने ही कश्मीर घाटी के लोगों के जान-माल की रक्षा की थी। सीमा पर संकट होता है तो सेना ही उससे जूझती है। कोई राजनीतिक दल युद्ध नहीं लड़ता। कम से कम सेना का मनोबल तो बनाए रखिए। जब विरोध की राजनीति करने वाले लोग सेना पर भी तंज कसने लगें तो इसे किस तरह की राष्ट्रवादिता कहा जाएगा?

कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। सरकार ने लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन किया था लेकिन लॉकडाउन की भावना को ही नकारा जाने लगा। प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर राजनीति कर सरकार को विवश कर दिया गया कि वह लॉकडाउन खोले। मजदूरों को उनके घर पहुंचाए और अब जब लॉकडाउन को खत्म करने का प्रथम चरण चल रहा है तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है। श्चित भी आपकी और पट भी आपकीश् का सिद्धांत आखिर कबतक चलेगा। विरोध की नहीं, देश की सोचिए। समस्या गिनाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता। समाधान बताया जाना चाहिए।

सियाराम पांडेय 'शांत'

अगर आपके पास समाधान है तो ही आप समस्या उठाने के अधिकारी हैं। समस्या उठी है तो उसके समाधान की जिम्मेदारी सरकार की होती है लेकिन इसके लिए उसे समय दिया जाना चाहिए। समस्या के समाधान में हाथ पर सरसों उगाने की बाजीगरी नहीं चलती। जनसेवा सत्ता में रहकर ही हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। जो जहां है, जिस हाल में है, वहीं से वह देश को आगे ले जाने और विकसित बनाने की पहल कर सकता है। इसके लिए बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होती है। पूर्वाग्रह और राग-द्वेष से भरा मन अपना भी नुकसान करता है और देश का भी। जो अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम देता है और उसमें राष्ट्र कल्याण की भावना रखता है, वही असली राष्ट्रवादी है।

देश की चिंता केवल हमें हैं, यह भाव ठीक नहीं है। देश सबका है, इसलिए इसके हित की चिंता भी सभी को करनी चाहिए और समस्या के समाधान का प्रयास भी उसी त्वरा के साथ किया जाना चाहिए। आलोचना और विवेक राष्ट्रधर्म के दो आयाम हैं। ये बहुत जिम्मेदारी की मांग करते हैं। शब्द की चोट सबसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए बोलने से पहले विचार कर लेने की भारतीय मान्यता है। अच्छा होता कि राजनीतिक दल राष्ट्रवाद की अनावश्यक बहस में पड़ने की बजाय आत्मपरिष्कार पर ध्यान देते। वे सोचते कि हम सुधरेंगे, तभी संसार सुधरेगा। केवल नसीहतों से देश नहीं चलता। जितनी मेहनत वे सरकार की आलोचना पर करते हैं, उतनी मेहनत में वे समाधान प्रस्तुत कर देते।

एक युवा अभिनेता का यूं चले जाना

आत्महत्या और नाकामी, दो ऐसे पहलू हैं जिनका आपस में गहरा संबंध होता है। नाकामी और असफलता मिलने पर व्यक्ति ऐसा करने को प्रेरित होता है। सुसाइट से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि जो इंसान अपनी लाइफमें फेल होता है, वह मौत को गले लगाता है। असफल व्यक्ति के लिए तब आत्महत्या अंतिम सहारा बनती है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर उठने वाले सवाल तब ठहर जाते हैं जब ऐसे कदम उठाने वाले को आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं? युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ऐसा ही मामला है।

अल्प अवधि में करियर में सफलता की बुलंदियां छूने वाले युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर अनायास संदेह होता है? बहुतेरे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज सुशांत की मौत पर आकर रूक रहे हैं। पुलिस का बयान आया है। बहुत ही जल्दी उन्होंने घटना को आत्महत्या करार दे दिया है। जबकि, घटना अनहोनी होने का संदेह पैदा करती है। आत्महत्या करने की कोई खास वजह भी दिखाई नहीं पड़ती। परिवार के लोग मानने को राजी नहीं हैं कि सुशांत ऐसा कायरतापूर्ण कदम उठाएगा। स्थिति को देखकर लगता है मामला पुलिस को नहीं, बल्कि फॉरेंसिक जांच को सौंपा जाए तभी कुछ निकलकर आ पाएगा। नहीं तो ये घटना भी दिव्या भारती और श्रीदेवी की मौत की तरह पहेली बनकर रह जाएगी।

जो करीब से जानते हैं उन्हें पता था कि सुशांत बहुत जिंदादिल अभिनेता थे। पढ़ाई-लिखाई में भी हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी। बिहार के पूर्णिया जिले के मलडीहा जैसे गांव से पटना तक पहुंचे एक नौजवान जो कि पढ़ने में इतना तेजतर्रार था कि पहली कोशिश में ही देशभर में 7वां स्थान पाकर टॉपर रहे। फिजिक्स में ओलंपियाड जीता हो, खेल जगत में भी आगे रहता हो। कहा जा रहा है कि सुशांत पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में थे और रोजाना दवाइयां लेते थे। अगर डिप्रेशन में थे भी तो कोई बड़ी बात नहीं, कई लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। पर, आत्महत्या तो कोई नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को बांद्रा के हिल रोड स्थित अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर मौजूद घर में फांसी लगाई। सुशांत में औरों को अपना बनाने की सबसे बड़ी खूबी थी। सामने वाले से तुरंत घुल-मिल जाते थे। उनमें घमंड-गुरूर, दूर-दूर तक नहीं था। सवाल यही है जिसका कैरियर टॉप पर हो, लाखों फॉलोअर्स हो, घर-परिवार में खुश होने के बावजूद कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम क्यों उठाएगा?

डॉ. रमेश ठाकुर

वैसे इंसान अक्सर हार-जीत, सफलता-असफलता के फेर में ऐसे फंस जाता है जिससे भूल जाता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी जिंदगी ही होती है। दरअसल, यह हमारी कमी है, हमारे इस आधुनिक समाज के बनाए ताने-बाने की वह फसलें हैं जिन्हें हम खुद बोते हैं। चार दिन पहले ही सुशांत राजपूत की मैनेजर की मौत हुई थी और अब सुशांत ने मौत को गले लगा लिया। दोनों की मौत में हो सकता है कोई सम्बंध हो ! निश्चित रूप से पुलिस दोनों की अनसुलझी कड़ियों को आपस में जोड़ेगी। सुशांत की मैनेजर की मौत हुई, तो व्यक्तिगत मामला मानकर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आधुनिक समाज में कहां किसी को समय है और हम भी तो अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने सतर्क होते हैं कि कोई हमारी परेशानी के बारे में पूछ ले तो बोलते हैं श्आपको क्या? हो सकता है मैनेजर की मौत से सुशांत परेशान हों, टूट चुके हों। लेकिन प्राइवेसी के सम्मान में किसी ने उनको समझने-समझाने की कोशिश नहीं की हो, नतीजा उनको अवसाद तक ले आया और आत्महत्या के मुहाने छोड़ दिया हो।

सुशांत ने हाल ही में छिछोरे नाम की फिल्म में भूमिका निभाई थी जो आत्महत्या जैसी कहानी पर केंद्रित थी। फिल्म में सुशांत ने सुसाइड की कोशिश करने वाले अपने बेटे को जीने का हौसला देने वाले पिता का रोल निभाया था। लेकिन उन्होंने जो रील में बताया वह असल जिंदगी में करके चले गए। दरकार अब इस बात की है सुशांत की मौत आत्महत्या है या हादसा, उचित जांच होनी चाहिए, माकूल निष्कर्ष निकलना चाहिए क्योंकि सच्चाई का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म जगत से जुड़े लोग क्यों आत्महत्या करते हैं यह स्थिति साफहोनी चाहिए। सुशांत की मौत पर जो संदेह जताया जा रहा है उससे पर्दा हटना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

कोरोना के इलाज में मुस्तैदी कैसे लाएं

दिल्ली में कोरोना-संकट से निपटने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने पहले दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से बात की और आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इन दोनों बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री डॉहर्षवर्द्धन, दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। सबसे अच्छी बात यह हुई कि प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस का प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुआ। यह क्या बताता है ? इससे पता चलता है कि भारत का लोकतंत्र कितनी परिपक्वता से काम कर रहा है। यह ठीक है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी तीरंदाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वे हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर सरकार की टांग खींचते है और जनता के नजरों में नीचे की तरफफिसलते जा रहे हैं लेकिन उन्होंने यह सराहनीय काम किया कि गृहमंत्री की बैठक में अपना प्रतिनिधि भेज दिया। गृहमंत्री की इन दोनों बैठकों में कुछ बेहतर फैसले किए गए हैं, जिनके सुझाव मैं पहले से देता रहा हूं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दिल्ली के अधिक संक्रमित इलाकों में अब घर-घर में कोरोना का सर्वेक्षण होगा। कोरोना की जांच अब आधे घंटे में ही हो जाएगी। रेल्वे के 500 डिब्बों में 8 हजार बिस्तरों का इंतजाम होगा। गैर-सरकारी अस्पतालों में 60 प्रतिशत बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। कोरोना-मरीजों को सम्हालने के लिए अब स्काउट-गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि संस्थाओं से भी मदद ली जाएगी।

मैं पूछता हूं कि हमारे फौज के लाखों जवान कब काम आएंगे ? कोरोना का हमला किसी दुश्मन राष्ट्र के हमले से कम है क्या ? यदि सिर्फ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5-6 लाख तक होनेवाली है तो उसका सामना हमारे कुछ हजार डॉक्टर और नर्स कैसे कर पाएंगे ? मुंबई में कोरोना की प्रारंभिक जांच सिर्फ25 रु. में हो रही है। कोरोना की इस जांच के लिए मुंबई की स्वयंसेवी संस्था 'वन रुपी क्लीनिक' की तर्ज पर हमारे सरकारी और गैर-सरकारी अस्पताल काम क्यों नहीं कर सकते ?

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

सरकार का यह फैसला तो व्यावहारिक है कि गैर-सरकारी अस्पतालों को सिर्फ कोरोना अस्पताल बनने के लिए मजबूर न किया जाए लेकिन हमारे सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में कोरोना-मरीजों के इलाज में लापरवाही और लूटमार न की जाए, यह देखना भी सरकार का कर्तव्य है। गृहमंत्री शाह खुद लो.ना. जयप्रकाश अस्पताल गए, यह अच्छी बात है। वहां के वीभत्य दृश्य टीवी पर देखकर करोड़ों दर्शक कांप उठे थे। यह आश्चर्य की बात है कि अभी तक सरकार ने कोरोना के इलाज पर होनेवाले खर्चों की सीमा नहीं बांधी है। मैं तो चाहता हूं कि उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाना चाहिए। हमारे देश में मामूली इलाज से ठीक होनेवालों की संख्या बीमार होने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। जिन्हें सघन चिकित्सा (आईसीयू) और सांस-यंत्र (वेंटिलेटर) चाहिए, ऐसे मरीजों की संख्या कुछ हजार तक ही सीमित है। कांग्रेस ने गृहमंत्री से कहा है कि गंभीर रोगियों को सरकार 10 हजार रु। की सहायता दे। जरुर दे लेकिन जरा आप सोचिए कि जो सरकार मरीजों का इलाज मुफ्त नहीं करा पा रही है, वह उन्हें दस-दस हजार रुपए कैसे देगी?

हर व्याख्या से ही निपट देते हैं देश की सारी समस्याएं

बिहार में भूकंप हुआ तो गांधी जी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हरिजनों के साथ जो पाप किया, उसका फल भोग रहे हैं।। अब यह जरा सोचने जैसा है। कितनी कठोर बात है! जैसे कि हरिजनों के साथ बिहार के लोगों ने ही बुरा काम किया हो। क्या यह सारा मुल्क बुरा काम नहीं कर रहा है हरिजनों के साथ?

अगर हरिजनों के साथ बुरा काम करने का फल भूकंप है तो इस पूरे हिंदु समाज को भी रसातल में चला जाना चाहिए था। इसके बचने का कोई कारण ही नहीं है इस पृथ्वी पर। उसने इतना अनाचार किया है, जिसकी गणना और हिसाब लगाना मुश्किल है। किसी आदमी को मार डालना बहुत बडा अपराध नहीं है, क्योंकि आदमी क्षण भर में मर जाता है, लेकिन किसी आदमी को हरिजन बना कर ुजदा रखना एक लबीं सजा है, जो सत्तर-अस्सी साल तक शूली पर लटकाए रखना है। उसका हिसाब लगाना मुश्किल है कि उसने कितना पाप किया है। वह अगर उसका फल था तो पूरे मुल्क को कभी का डूब जाना चाहिए। जमीन पर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बिहार में भूकंप आया, वहां लोग तकलीफमें पडे तो गांधी जी ने व्याख्या कर ली कि वहां कि लोगों ने हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसका फल वे भोग रहे थे। अब सोचो, इस व्याख्या को सुन कर भूकंप की जो पीडा है, वह एकदम विदा हो जाती है? में नहीं कहता कि व्याख्या सही या गलत है, यह सवाल नहीं है बडा। सवाल यह है कि जैसे हमने सुना है कि भूकंप इसलिए पडा कि उन लोगों ने पाप किया था और उसका फल भोगा उन्होंने, वैसे ही, वह जो दुख भोग रहा है, उसके प्रति हमारा भाव बदल गया है, बुनियादी रूप से बदल गया है, उसके हमारे बीच एक खाई का फासला हो गया है। तब हमें बिलकुल ऐसा लगेगा कि ठीक ही हो रहा है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने जीवन के रहस्यपूर्ण तथ्यों की काल्पनिक व्याख्याएं कर ली हैं।, उन लोगों ने कठोर दुनिया निर्मित की है। जैसे मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में हमने बहुत कठोर समाज निर्मित किया है, क्योंकि हमने प्रत्येक चीज की व्याख्या खोज ली है। व्याख्या की वजह से सब कठोर और जड हो गया। कोई गरीब है तो हमने व्याख्या खोज ली कि अपने पाप का फल भोग रहा है। कम उम्र में मरा तो हमने कहा कि उसने अपने किसी पाप का फल भोगा है। दुखी है, पींडित है, अंधा है, लंगडा है, लूला है तो हमने सोचा कि अपने पाप का फल भोग रहा है। हमने जब-जब व्याख्या कर ली, तब-तब पीडा की जो गहराई थी, उससे हम बच भागे।

गांधी तो अभी भी प्लेटफार्म पर ही है, उनका केवल देश बदला है!

श्रवण गर्ग, लेखक

अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान 'व्हाइट हाउस' के सामने की एक सड़क का नाम बदलकर 'ठसंबा स्पअमे डंजजमत'(अश्वेतों का जीवन मायने रखता है) कर दिया गया है। पांच जून को दिन के उजाले में बड़े-बड़े शब्दों में समूची चौड़ी सड़क (16जीं जतममज) को इन शब्दों से पीले रंग से ढक दिया गया। नाम में कहीं भी अंग्रेजी के '।सेव' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।व्हाइट हाउस की आँखों से आँखें मिलाते हुए ऐसा करने का साहस वाशिंगटन डीसी की महापौर (मेयर) मरेल इ बौसर ने दिखाया है। दुनिया भर की सत्ताओं को अपनी अंगुलियों पर नचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही शहर और देश की राजधानी की महापौर के इस साहसिक कदम को रोक नहीं पाए। उनका काफिला अब जितनी भी बार इस सड़क से गुजरेगा जॉर्ज फ्लायड नामक एक साधारण से अश्वेत नागरिक की एक गोरे पुलिसकर्मी के घुटने के नीचे हुई मौत का दृश्य टकराता रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सड़कों से खदेड़ने के लिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया है पर सड़क पर लिखा हुआ नाम अब हमेशा क़ायम रहने वाला है।

क्या भारत में ऐसा सम्भव है या कभी हो सकेगा कि राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास के आसपास या कहीं दूर से भी गुजरने वाली सड़क को करोड़ों प्रवासी मजदूरों के जीवन के नाम पर कर दिया जाए ? नजर नहीं आने वाले अत्यंत ही बारीक अक्षरों में लिख दिया जाए किरू'मजदूरों की जिंदगी मायने रखती है ÷।ऐसा न तो 'मुमकिन' है और न ही कोई ऐसी माँग भी करेगा।प्रवासी मजदूरों की व्यथा को ऊँची आवाज में उठाने वाले राहुल गांधी भी नहीं जिनके कि पिता, दादी और नाना के नामों से देश भर की इमारतें, संस्थान और चौराहे पटे पड़े हैं।और फिर 'न्यू इंडिया' में तो इस समय केवल नामों को ही बदलने का उपक्रम चल रहा है ! देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष दिल्ली के एक नागरिक की याचिका विचाराधीन है कि अंग्रेजी में भी देश का नाम 'प्दकपं' के बजाय 'ठींतंज' या 'भ्पदकनेजंद' होना चाहिए।प्रधानमंत्री की तो ढेर सारी योजनाओं और परिकल्पनाओं के नाम ही अंग्रेजी भाषा में हैं।हम शहरों, सड़कों, संस्थानों और इमारतों के नाम बदलने में लगे हुए हैंय पुराने इतिहास में संशोधन कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देश और उनके नागरिक नया इतिहास रचने में जुटे हैं।नामों को तो वे भी बदल रहे हैं पर उनकी इबारत पीड़ा और आंसुओं से तराशी जा रही है, धर्म और राजनीति से नहीं।

कोई साढ़े चार सौ साल पहले अंग्रेजी के महान कवि और नाटककार विलियम शैक्सपियर ने कहा था किरू'नाम में क्या रखा है !' अमेरिका के सैंकड़ों शहरों और दुनियाभर की राजधानियों में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उससे साबित हो रहा है कि नाम में बहुत कुछ रखा है ।नाम फिर चाहे (तब) अज्ञात मोहनदास करमचंद गांधी का हो जिसे सवा सौ साल पहले अश्वेत होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के एक स्टेशन (पीटरमारित्जबर्ग) के प्लेटफॉर्म पर रेल के डिब्बे से धक्के मार कर उतार दिया गया था या फिर साधारण अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड का हो जिसे अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में 25 मई को दिन दहाड़े मार दिया गया था।दक्षिण अफ्रीका की घटना भी नस्लवाद से प्रेरित थी और अमेरिका की घटना भी।गांधी को धक्के देकर रेल के डिब्बे से निकलने के कोई सौ साल बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका को तो रंगभेद की नीति से आजादी मिल गई पर अमेरिकी अश्वेत दो सौ सालों के बाद भी समान नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष में लगे हैं।हमारे यहाँ 'निर्जीव' चीजों के नाम बदले जा रहे हैं और समान नागरिक अधिकारों की माँग करने वाली 'सजीव' आत्माओं को देशद्रोही करार दिया जा रहा है।

वाशिंगटन में हाल ही में कुछ 'अज्ञात' शरारती तत्वों ने भारतीय दूतावास के सामने स्थापित गांधीजी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था।घटना दो जून की रात की है।भारतीय दूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग और अन्य स्थानीय एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करा दी है और जाँच भी चल रही है।नई दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने घटना के लिए क्षमा याचना भी की है।हमारे पास इस सवाल का क्या जवाब है कि देश में ही गांधी के विचारों और आस्थाओं की 'ज्ञात' क्षेत्रों के द्वारा रोजाना खुले आम हत्या क्यों हो रही है और दर्ज होने वाली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? याद किया जा सकता है कि आज ही के दिन यानी सात जून 1893 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के एक रेल्वे स्टेशन पर धक्के देकर प्लेटफॉर्म पर फेंका गया था। गांधी अभी भी प्लेट फॉर्म पर ही हैं। देश बदल गए हैं।

गरीब होने का विशेषाधिकार

निर्मल असो, स्वतंत्र लेखक

भारत में गरीब होना और गरीब साबित होने में भले ही अंतर है, लेकिन जिसे बीपीएल परिवार घोषित होने का गौरव हासिल हो गया, उसके पास आकर देश का लोकतांत्रिक चरित्र हमेशा पानी भरेगा। जो एक बार गरीब साबित हो गया, उस पर प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के बजट को कुर्बान होने का मौका मिलता है, बल्कि सियासत के सारे पाप ऐसे गरीबों के पास आकर ही धुल जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि सारे बीपीएल परिवार गरीब हैं, तो आप समूची गरीबी की तौहीन करेंगे। दरअसल अपने देश में गरीबी का अर्थ बदल गया है यानी जो ईमानदारी से आयकर देता है, लगातार जीएसटी भरता है, नौकरी में रिश्वत नहीं लेता और सरकार के आदेशों-लालफीताशाही के वर्चस्व को कबूल करता है, वह अव्वल दर्जे का गरीब है। अब यही गरीबी रहेगी, जो देश के आंकड़ों में अदृश्य रहेगी। गरीबी दरअसल पैशन है, भारतीय फैशन है। किसी बीपीएल को उठा कर देखो, नहीं उठ पाएगा। अगर यह आसान होता, तो आजादी के 73 वर्षों में गरीबी की कोई लाइन नहीं बचती। वैसे देखा जाए तो यह अच्छा ही है कि गरीबी के कारण राजनीति को अपना मेहनताना मिलता है। दरअसल गरीबी के कारण ही राजनीति इतनी गरीब हो गई कि इसे हर मतपत्र भी गरीब दिखाई देने लगा। आश्चर्य यह कि भारत में जो व्यक्ति खुद को गरीब साबित न कर पाए, वही असल में गरीब है वरना रिलायंस को ही देखें कि जब देशभर के मजदूरों को काम नहीं रहा, यही एकमात्र कंपनी है जो अपनी दरिद्रता दूर करने की कोशिश से हर जगह से उगाही कर पा रही है। दरअसल देश की गरीबी को दूर करने के लिए उगाही ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए आपके आसपास अगर कोई उगाही कर रहा है, तो इससे आपकी गरीबी जरूर दूर होगी। हर नेता, नौकरशाह और प्रभावशाली अधिकारी को मालूम है कि उगाही जैसा परोपकारी काम इस जीवन में शायद ही दोबारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका ने एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी करके बता दिया कि अब उगाही का भविष्य क्या है। इसी तरह जो लोग एक साथ सरकारी योजनाओं की उगाही कर पा रहे हैं, वही देश को सफल बना रहे हैं, वरना सरकारों को तो कोई काम ही न मिले। गरीब होंगे, तभी तो सरकारें होंगी। इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का शाश्वत नारा देकर आज तक की सरकार को भी काम पर लगाए रखा है। गरीब न होते, तो सरकार के पास करने को शायद कुछ नहीं बचता और इस स्थिति में नेताओं को मसीहा कौन मानता। हमारे बुजुर्गों ने सोच-समझ कर ही नेताओं पर भरोसा किया ताकि बदले में हमारी गरीबी का राष्ट्रीय इश्तिहार बना रहे। भले ही लोग जीएसटी देते रहें या आयकर के छापे पड़ते रहें, लेकिन देश में जब तक हम बीपीएल परिवार में हैं, न कोई हमें उठा सकता है और न ही हमारे बगैर किसी चुनाव का मुद्दा बना सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में हमेशा गरीबी की सत्ता रहेगी और यह बदस्तूर जारी है।

गांवः आर्थिक संयम की संस्कृति के केंद्र

गांव भारत की प्रशासनिक लोकतांत्रिक इकाई है और वैदिक काल से ही सांस्कृतिक इकाई भी। ग्रामों के आत्मीयता के बन्धन मधुर हैं। ऋग्वेद में भी ग्रामों की प्रतिष्ठा है। उस समय भी गांव सांस्कृतिक इकाई थे। ऋग्वेद में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा गया है। भारत को गॉवों का देश कहा जाता रहा है। ग्राम इकाई जर्मनी में भी थी। वहॉ इस इकाई को मार्क कहा जाता था। गॉधीजी गाँवों को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के पक्षधर थे लेकिन स्वतंत्र भारत में गांव की समृद्धि की उपेक्षा हुई। गांव कृषि और पशुपालन से ही अपनी रोजी-रोटी चलाते थे। कृषि क्षेत्र से जुड़े उपकरणों को बनाने वाले अन्य उपयोगी वस्तुओं के कारीगर गांव में प्रतिष्ठित थे। इसके बावजूद गांव में रोजगार के अवसर नहीं थे। गांव के श्रमिक रोजगार के लिए महानगरों व अपने राज्यों के तुलना में अन्य विकसित राज्यों की ओर जाने लगे। श्रमिक अन्य देशों की ओर भी गये। अंग्रेजी राज्य में विशेष अनुबन्ध या एग्रीमेंट के माध्यम से वे अन्य देशों में भी गये। एग्रीमेंट के बन्धन के कारण उनका नाम गिरमिटिया मजदूर पड़ा। खाड़ी के देशों में भी भारत के ढेर सारे श्रमिक काम करते रहे हैं। भारत के भीतर अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर रुख करने वाले श्रमिक अपना गांव नहीं भूले। वे महानगरों में कमाते थे और खाने-पीने से बचाया गया धन अपने परिवार को भेजते थे।

कोरोना आपदा ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। जीविका के साथ जीवन का भी संकट आया। सबको अपने घर और गांव की सुधि आयी। देश के सभी राज्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार चिन्ता की लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के अन्य राज्यों की तुलना में महत्वपूर्ण काम किया है। उत्तर प्रदेश के लाखों प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में थे। सभी मजदूर अपने गांव घर पहुँचने की शीघ्रता में थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्धस्तर पर सबको घर पहुँचाया। प्रवासी श्रमिकों की चिन्ता नई चेतना का विषय बना है। मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन की भी घोषणा की है। उन्होंने पूरे राज्य में श्रमिकों की कुशलता का अध्ययन करवाने का फैसला लिया है। यह काम चल रहा है। श्रमिकों को अपने गांव, क्षेत्र, जिला और राज्य में ही रोजगार देने के मुख्यमंत्री के फैसले से राज्य के श्रमिक उत्साहित और प्रसन्न हैं। सरकार की संवेदनशीलता राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों द्वारा सेवाएं दी जाती रही हैं। योगी ने सभी श्रमिकों को काम देने का निर्णय, क्रियान्वित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। अन्य राज्य चिन्तित हैं कि उन्हें कर्मठ और ईमानदार श्रमिकों की सेवायें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पायेंगी।

गांव आर्थिक संयम की संस्कृति के केन्द्र हैं। गांव वाले गंवई और गंवार भी कहे जाते हैं। गंवार का अर्थ नासमझ से लिया जाता रहा है, लेकिन गंवार का असली अर्थ गांववाला है। गांव की परिभाषा और व्याख्या करना आसान नहीं है। यहाँ अभाव के बावजूद संतोष के छन्द हैं। गांव का अपना व्यक्तित्व है। दुनिया के सभी महानगर ग्रामीण श्रमिकों की कृषि उत्पादन शक्ति और महानगरों के निर्माण करने वाली श्रम शक्ति का परिणाम है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास और निर्माण नगरीय सभ्यता ने नहीं किया। इसके पीछे सिंधु, सरस्वती के विशाल भू-भाग में फैले गाँवों की श्रमशक्ति का ही कौशल रहा है। गांव के लोग शत प्रतिशत आस्तिक हैं। अपने श्रम के विश्वासी हैं। वे आस्थावादी हैं। अध्यात्मवादी भी हैं।

गाँवों में विचार विविधता है। गांव के हर मोहल्ले में अपने ढंग की संसद चलती है। दस-पाँच लोग यों ही खाली समय में बैठते हैं। सुख-दुःख की चर्चा करते हैं और जाने-अनजाने विषयों पर बहस करते हैं। मैं स्वयं गांव का हूँ। बचपन में ऐसी बहसों का श्रोता रहा हूँ। बाद में 15-16 वर्ष की उम्र का होते-होते ऐसी गोष्ठियों में सदस्य के रूप में हिस्सा भी लेता रहा हूं। हमारा विद्यार्थी मन कहता है कि मोहल्ले-मोहल्ले होने वाली गपबाजी के समूह को पार्लियामेंट कहना ज्यादा सही होगा। ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्ले शब्द का अर्थ होता है- चबाना, कुटकना मुँह के भीतर घुमाना। हमारे गांव की पार्लियामेंट मजेदार थी। मैं उसे अभी भी नहीं भूल पाया हूं। वैसे यह गपबाजी थी। इसके विषय अपने आप तय हो जाते थे। एक सायं चन्द्रमा के चारों ओर बादलों का घेरा दिखायी पड़ा। हमारी गांव की संसद में बहस थी कि यह घेरा अनिष्ट की सूचना है। अगले ने कहा कि यह वर्षा की सूचना है, एक ने कहा कि आंधी भी साथ आ सकती है। ग्राम संसद की बहसें मजेदार थी। हमारे बचपन में हमारे गांव में कोई चाय नहीं पीता था। शहर से गांव लौटे एक प्रवासी ने चाय पीना और पिलाना शुरू किया। गांव की संसद में बहस थी कि चाय पीने से व्यक्ति की ताकत घट जाती है। अगले ने कहा कि चाय तत्काल ताकत देती है। दूसरे ने बात काटी कि यह बड़े लोगों के चोचले हैं। अभी तो हमारे गांव में चाय आयी है और आगे अंग्रेजी दारू भी आयेगी। यह निर्णय सुनाने वाले ने तम्बाकू खाई, अगले ने कहा तम्बाकू खाना क्या अच्छा है। एक पंडित जी ने कहा कि तम्बाकू देवलोक में नहीं होती है। देवता भी तम्बाकू के लिए पृथ्वी पर आते हैं।

हृदयनारायण दीक्षित

गांव की बहसें अब बदल गयी हैं। महानगरों से गांव लौटे प्रवासी श्रमिक बहस का विषय हैं। पहले शहर से गांव लौटे मजदूर से सब लोग हालचाल लेते थे, अब डर लगता है कि यह कोरोना लेकर तो नहीं आया है। प्रवासियों के आते ही डर बढ़ जाता है। गांव में टीवी-रेडियो पहुँच गए हैं। इसके कारण बहस के विषयों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार-बार चर्चा का केन्द्र बनते हैं। लाखों मजदूरों को घर लाना छोटा काम नहीं है। मुख्यमंत्री की प्रशंसा हो रही है कि यह काम योगी जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता था। गरीबों के बैंक खाते में सीधे रुपये भेजने की चर्चा भी रोज होती है। गांव में ही रोजगार देने की उम्मीद से महामारी के बावजूद नया आशावाद फैला है। देश के अन्य राज्यों ने भी उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाया है। गांव की राजनैतिक बहसें भी उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की प्रशंसा की ओर मुड़ गयी हैं।

आशा में उत्साह होता है और निराशा में विषाद। आशा से सपने पैदा होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लिये जाते हैं। संकल्प को पूरा करने के लिए योजनाएं बनानी होती हैं। इसके लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। महामारी के कारण लड़ाई के कई मोर्चे बन गये हैं। इसके बावजूद श्रमिकों की समग्र समस्याओं की चिन्ता से नयी रौनक लौटी है। रोजगार विषयक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए खासे समय की जरूरत होती है लेकिन काम शुरू हो गया है। अल्प समय में बाधायें दूर करते हुये गरीबों के मन में आशा और उत्साह भरने का काम वाकई आश्चर्यजनक है। संवेदनशीलता से बड़ा दूसरा मानवीय गुण नहीं होता। महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से जूझने में संवेदनशीलता का ही महत्व है। यहाँ संवेदनशीलता के साथ-साथ सह-अनुभूति भी है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं।)

चीन से बढ़ता आयात

भरत झुनझुनवाला, आर्थिक विश्लेषक

भारत की संप्रभुता पर चीन से खतरा मंडरा रहा है। चीन के साथ हमारा व्यापार का घाटा तो पहले ही बढ़ रहा था यानी हमारे चीन को निर्यात कम और आयात अधिक थे। इसके अतिरिक्त चीन से भारी मात्रा में भारत में निवेश भी आ रहा है। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था पर चीन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इस परिस्थिति में देश के एक वर्ग का मानना है कि भारतीय नागरिकों को चीन का माल खरीदने से बचना चाहिए। उनकी यह बात बिलकुल सही है, लेकिन भारत सरकार स्वयं चीन के साथ-साथ दूसरे देशों से माल के आयात एवं पूंजी के निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। समस्या यह है कि पूरे विश्व के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलें और चीन से उसे अलग करें, ऐसा संभव नहीं है। यदि हम सीधे चीन के माल और निवेश रोकते हैं तो भी वह घूमकर अपने देश में प्रवेश करेगा ही। अतः यदि हमको चीन से माल के आयात एवं पूंजी निवेश को रोकना है तो दूसरे देशों से भी माल के आयात और निवेश को रोकना पड़ेगा और संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हर देश ने वचन दे रखा है कि वह अधिकतम कितना आयात कर आरोपित करेगा। भारत ने डब्ल्यूटीओ में वचन दिया है कि वह औसतन 48.5 प्रतिशत से अधिक आयात कर नहीं आरोपित करेगा। इसकी तुलना में वर्तमान में भारत ने केवल 13.8 प्रतिशत आयात कर लगा रखा है यानी डब्ल्यूटीओ में दिए गए वचन के अंतर्गत ही हम अपने आयात कर में तीन गुना वृद्धि कर सकते हैं और चीन समेत दूसरे देशों से माल के आयात को रोक सकते हैं। माल के आयात का विषय विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण के ये दो पैर हैं। जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को माल के आयातों के लिए खोलते हैं तो साथ-साथ विदेशी निवेश के लिए भी खोल देते हैं जिससे कि हमें आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हो जाएं और हम भी उत्तम क्वालिटी का माल बना कर आयातों के सामने खड़े रह सकें।

बताया जाता है कि वर्ष 2019-20 में भारत को 49 अरब डालर का विदेशी निवेश आया है, लेकिन यह आंकड़ा भ्रामक है। ग्लोबल फाइनांशियल इंटेग्रिटी नामक स्वतंत्र वैश्विक संस्था ने अनुमान लगाया है कि भारत से 9.8 अरब डालर की रकम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से गैर कानूनी ढंग से विदेश भेजी जा रही है। जैसे यदि किसी कंपनी के लंदन और मुंबई में दफ्तर हैं तो मुंबई शाखा द्वारा निर्यात किए गए माल का दाम कम बताया जाता है। 10 रुपए के माल का आठ रुपए में निर्यात कर दिया जाए तो भारत को दो रुपए कम मिलेंगे अथवा दो रुपए जो मिलने थे वे नहीं मिलेंगे अथवा दो रुपए बाहर चले जाएंगे। इस प्रकार भारत से रकम लंदन को चली जाती है। हमारी पूंजी का बाहर जाने का दूसरा रास्ता भारतीय उद्यमियों द्वारा दूसरे देशों में विदेशी निवेश है। अपने देश से 11.3 अरब डालर की रकम गत वर्ष बाहरी विदेशी निवेश के रूप में भारत से दूसरे देशों को कानूनी ढंग से बाहर गई है। तीसरा रास्ता राउंड ट्रिपिंग का है। कई भारतीय उद्यमी भारत में अर्जित रकम को हवाला के माध्यम से पहले विदेश भेज देते हैं। वहां उसे सफेद रकम में बदलकर वापस भारत को विदेशी निवेश के रूप में ले आते हैं। जैसे किसान अपनी सब्जी को मंडी में बेचे और घरवाले उसी सब्जी को खरीदकर वापस ले आएं। इस प्रकार अपनी ही रकम भारी मात्रा में विदेशी निवेश के रूप में घूमकर अपने देश में आ रही है। इस माध्यम से कितनी रकम आ रही है, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल इतना स्पष्ट है कि 49 अरब डालर का जो विदेशी निवेश आया बताया जा रहे हैं, उसमें 20 अरब डालर तो स्पष्ट रूप से बाहर जा ही रहा है। इसके अलावा अपनी पूंजी घूमकर वापस आ रही है। इस मद से 40 अरब डालर बाहर जा रहे हों तो कुल पलायन 60 अरब डालर का हो जाएगा, जबकि केवल 49 अरब डालर आ रहे हैं। वास्तव में अपनी पूंजी बाहर जा रही है। यही हमारी गिरती विकास दर का एक कारण है। इस प्रकार वैश्वीकरण को अपना कर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी माल के आयात और अपनी पूंजी के निर्यात के लिए खोल दिया है। हमारी सरकार इस दुर्व्यवस्था पर रोक क्यों नहीं लगाती है? मेरे आकलन में इसके चार कारण हैं। पहला कारण हमारे मध्यम वर्ग को सस्ते विदेशी माल को उपलब्ध करने का सरकार का उद्देश्य है। इसलिए सरकार चीन आदि में बने हुए सस्ते माल के आयात पर अधिक आयात कर नहीं लगाना चाहती है। दूसरा कारण भारतीय उद्यमियों द्वारा चीन समेत दूसरे देशों में निवेश है। कन्फेडरेशन ऑफइंडियन इंडस्ट्री की एक रपट के अनुसार कम से कम 54 भारतीय कंपनियों ने चीन में निवेश कर रखा है। इनमें से लगभग 30 कंपनियों के चीन में 50 से अधिक श्रमिक थे और तीन कंपनियों के 1000 से अधिक श्रमिक थे। जाहिर है कि इन कंपनियों द्वारा चीन में भारी माल का उत्पादन किया जा रहा है। उसमें से कुछ माल संभवतः भारत में प्रवेश करता होगा। इसलिए इन भारतीय निवेशकों का दबाव भारत सरकार पर दिखता है। यदि भारत सरकार द्वारा चीन से आयातित माल पर अधिक आयात कर लगाए जाएंगे तो इन कंपनियों द्वारा चीन में उत्पादित माल पर भी संकट आएगा। तीसरा कारण यह है कि भारतीय कंपनियां भारी मात्रा में भारत से रकम को विदेश भेजने को उत्सुक हैं, जैसे टाटा ने इंग्लैंड में जगुआर कंपनी को खरीदा था। इस खरीद के लिए भारतीय उद्यमियों का भारत सरकार पर दबाव रहता है कि विदेशी निवेश पर अंकुश न लगाया जाए। चौथा कारण यह दिखता है कि सरकारी कर्मियों को विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सेवानिवृत्ति के बाद मोटी सलाहकारी मिलती है। भारत सरकार के एक पूर्व सचिव ने मुझे बताया था कि उन्हें 40 हजार प्रति घंटा की विश्व बैंक ने सलाहकारी का ठेका दे रखा था। इस प्रकार के व्यक्तिगत ठेकों के प्रलोभनों में वर्तमान सरकारी अधिकारी विदेशी निवेश और विदेशी आयात को रोकने की चेष्टा के प्रति उदासीन रहते हैं क्योंकि इनकी नजर अपने ही भविष्य के ठेकों पर रहती है। इसी कारण भारत सरकार न तो विदेशों से आने वाले माल पर रोक लगाती है, न ही अपनी पूंजी के पलायन पर रोक लगाती है। लेकिन देश की जनता को एहसास कराती है कि वह चिंतित है और जनता का आह्वान करती है कि वह चीन का माल न खरीदे, जबकि सरकार स्वयं उसी माल के आयात को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

मानव जीवन के अस्तित्व का आधार है प्रकृति

डॉ. शंकर सुवन सिंह, लेखक

मानव प्रकृति का हिस्सा है।प्रकृति व मानव एक दूसरे के पूरक हैं ।प्रकृति के बिना मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती।प्रकृति दो शब्दों से मिलकर बनी है - प्र और कृति।प्र अर्थात प्रकृष्टि (श्रेष्ठध्उत्तम) और कृति का अर्थ है रचना ।ईश्वर की श्रेष्ठ रचना अर्थात सृष्टि।प्रकृति से सृष्टि का बोध होता है ।प्रकृति अर्थात वह मूलत्व जिसका परिणाम जगत है।कहने का तात्पर्य प्रकृति के द्वारा ही समूचे ब्रह्माण्ड की रचना की गई है। प्रकृति दो प्रकार की होती है- प्राकृतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। प्राकृतिक प्रकृति में पांच तत्व - पृथ्वी , जल अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं।मानव प्रकृति में मन , बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थ श्रीमद् भगवद्गीता में वर्णित(सातवां वां अध्याय व चौथा श्लोक) दृ भुमिरापोनलो वायुरू खं मनो बुद्धि रेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।गीता 7रू4 ।। अर्थ रू भगवान् श्री कृष्ण गीता में कहते हैं -पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पञ्चमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार- यह आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी श्अपराश् प्रकृति है। हे महाबाहो ! इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवरूप बनी हुई मेरी श्पराश् प्रकृतिको जान, जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य- ये आठ प्रकार की प्रकृति समूचे ब्रह्माण्ड का निर्माण करती है।वेदों में वर्णित है की ष्मनुष्य का शरीर पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है।ष् इन पंचतत्वों को विज्ञान भी मानता है। अर्थात मानव शरीर प्राकृतिक प्रकृति से बना है ।प्रकृति के बगैर मानव अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । मानव का मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनो प्रकृति को संतुलित या संरक्षित करते हैं।प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत, सूर्य-चांद-तारे दीपक, सागर-नदी पानी के मटके और पेड़-पौधे आहार के साधन हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया वह सब प्रकृति से सीखकर ही किया है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने सिखाए हैं तो वहीं कवियों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर एक से बढ़कर एक कविताएं लिखीं। इसी तरह आम आदमी ने प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। जैसे-पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इसी तरह फलों से लदे, मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है, जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा-सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्यपुराण में एक वृक्ष को सौ पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहां वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता-फूलता है, जितने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष फलते-फूलते हैं।

प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपनी चीजों का उपभोग स्वयं नहीं करती। जैसे-नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है। जिसे वह समय-समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है ।

जल,जंगल और जमीन विकास के पर्याय हैं।जल,जंगल और जमीन जब तक है तब तक मानव का विकास होता रहेगा। मानव जो छोड़ते हैं उसको पेड़ -पौधे लेते हैं और जो पेड़-पौध छोड़ते हैं उसको मानव लेते हैं।जल ,जंगल और जमीन से ही जीवन है।जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास अर्थात बिजली,सड़क ,आदि किसी काम के नहीं रहेंगे।यह कहने में आश्चर्य नहीं होगा कि समुदाय का स्वास्थ्य ही राष्ट्र की सम्पदा है।जल,जंगल और जमीन को संरक्षित करने लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरुरी है। मन आतंरिक पर्यावरण का हिस्सा है।जल,जंगल और जमीन वाह्य (बाहरी) पर्यावरण का हिस्सा है।हर धर्म ने माना प्राकृतिक विनाश से विकास संभव नहीं है।वैदिक संस्कृति का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध है। वैदिक संस्कृति का सम्पूर्ण क्रिया-कलाप प्राकृत से पूर्णतःआवद्ध है। वेदों में प्रकृति संरक्षण अर्थात पर्यावरण से सम्बंधित अनेक सूक्त हैं।वेदों में दो प्रकार के पर्यावरण को शुद्ध रखने पर बल दिया गया हैदृआन्तरिक एवं बाह्य। सभी स्थूल वस्तुऐं बाह्य एवं शरीर के अन्दर व्याप्त सूक्ष्म तत्व जैसे मन एवं आत्मा आन्तरिक पर्यावरण का हिस्सा है। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान केवल बाह्य पर्यावरण शुद्धि पर केन्द्रित है। वेद आन्तरिक पर्यावरण जैसे मन एवं आत्मा की शुद्धि से पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करता है।बाह्य पर्यावरण में घटित होने वाली सभी घटनायें मन में घटित होने वाले विचार का ही प्रतिफल हैं। भगवद् गीता में मन को अत्यधिक चंचल कहा गया है दृ चंचलं ही मनः ड्डष्ण ।।।। (भगवद् गीता 6रू34)। बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण एक दूसरे के अनुपाती हैं। जितना अधिक आन्तरिक पर्यावरण विशेषतया मन शुद्ध होगा, बाह्य पर्यावरण उतना अधिक शुद्ध होता चला जायेगा। वेदों के अनुसार बाह्य पर्यावरण की शुद्धि हेतु मन की शुद्धि प्रथम सोपान है। इन तत्वों में किसी भी प्रकार के असंतुलन

का परिणमा ही सूनामी, ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खल, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदायें हैं वेदों में प्रकृति के प्रत्येक घटक को दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही अग्नि को समर्पित है - ऊँ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । (ऋग्वेद 1।1।1) ऋतं ब्रह्मांड का सार्वभौमिक नियम है। इसे ही प्रकृति का नियम कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार दृ सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः त्रृतेनादित्यास्तिठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः ऋग्वेद (10रू85रू1) भावार्थ दृ देवता भी ऋतं की ही उत्पति हैं एवं ऋतं के नियम से बंधे हुए हैं। यह सूर्य को आकाश में स्थित रखता है। वेदों में वरूण को ऋतं का देवता कहा गया है । वैसे तो वरूण जल एवं समुद्र के वेता(वरुणस्य गोपः) के रूप में जाना जाता है परन्तु मुख्यतया इसका प्रमुख कार्य इस ब्रह्मांड को सुचारू पूर्वक चलाना है।ऋग्वेद में वनस्पतियों से पूर्ण वनदेवी की पूजा की गई है दृ आजनगन्धिं सुरभि बहवन्नामड्डषीवलाम् प्राहं मृगाणां मातररमण्याभिशंसिषम् (ऋग्वेद 10रू146रू6) भावार्थ दृ अब मैं वनदेवी (आरण्ययी) की पूजा करता हूँ जो कि मधुर सुगन्ध से परिपूर्ण है और सभी वनस्पतियों की माँ है और बिना परिश्रम किये हुए भोजन का भण्डार है।छान्दोग्यउपनिषद् में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भाँति सुख-दुरूख की अनुभूति करते हैं। तुलसी का पौधा मनुष्य को सबसे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण भी मौजूद हैं।पीपल को देवता मानकर भी उसकी पूजा नियमित इसीलिए की जाती है क्योंकि वह भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। गुरु ग्रन्थ साहिब में वर्णित है -ष्पवन गुरु,पानी पिता,माता धात महत ष्अर्थात हवा को गुरु ,पानी को पिता तथा धरती को माँ का दर्जा दिया गया है।आपदाएं प्राकृतिक हों या मानव निर्मित दोनों आपदाओं में मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।सभी आपदाएं मानवीय असफलता का परिणाम होती हैं।मानवीय कार्य से निर्मित आपदा- लापरवाही,भूल या व्यवस्था की असफलता,मानव निर्मित आपदा कहलाती है।एक प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी ,विस्फोट या भूकंप भी मनुष्य की सहभागिता के बिना भयानक रूप धारण नहीं करते।मानव निर्मित आपदा में बम विस्फोट ,रासायनिक ,जैविक रेडियोलॉजिकल ,न्यूक्लिअर,रेडिएशन आदि आपदाएं आती हैं ।कोरोना महामारी जैविक आपदा का ही हिस्सा है।इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना (कोविड-19) वायरस का संक्रमण इतना भयावह है की इससे पीड़ित मनुष्य व उसके मृत शरीर के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोविड- 19 वायरस के अधिक से अधिक देशों में फैलने से लोगों को अधिक चिकत्सीय देखभाल की जरुरत पड़ रही है जिस वजह से डिस्पोजेबल फेस मास्क और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है फलस्वरूप चिकित्सा अपशिष्ट भी बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर चीन, प्रयोग हुए फेस मास्क और मेडिकल कचरे से जूझ रहा है।सिर्फचीन के वुहान में चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा एक दिन में 200 टन से अधिक है।विश्व में लॉक डाउन के दौरान लोगों ने अपने आप को आइसोलेट (अलग) कर लिया उसका परिणाम यह हुआ की बिजली की खपत बढ़ गई ।भारत में बिजली बांध के माध्यम से जल को ऊँचाई पर भण्डारित करके तथा उसे नियन्त्रित रूप से टर्बाईन से गुजारकर जल विद्युत पैदा की जाती है। भारत में जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 22 फीसदी बिजली का उत्पादन होता है ।कोरोना महामारी आपदा के दौरान लोगों ने जल का सेवन अत्यधिक शुरू कर दिया।जल के दोहन से जल संरक्षण में कमी आई।कोरोना महामारी से एक तरफलोगों का लॉक डाउन में रहने के दौरान प्रदूषण कम हुआ ,नदियां साफ हुई,ओजोन लेयर की परत ठीक हुई आदि चीजे मानव के शुद्धिकरण से फलित हो पाई हैं।न की इसमें कोरोना का कोई योगदान है। कोरोना महामारी के डर से मानव शुद्ध हुआ है।मानव शुद्ध हुआ तो पर्यावरण शुद्ध हुआ ।यही चीजें महामारी के ना आने पर भी की जा सकती थी।यदि मानव पहले से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहे तो कोई भी आपदा विकराल रूप धारण नहीं करेगी।कहने का तात्पर्य यह है कि आपदा कैसी भी हो वो मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।मानव प्रकृति ,प्राकृतिक प्रकृति पर हावी है ।मन,बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो तो मानव,प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं पर नियंत्रण पा सकता है ।चीन देश मन ,बुद्धि और अहंकार से अशुद्ध है अतएव उसने जैविक आपदा को जन्म दिया।आज सारा विश्व चीन के मानव निर्मित जैविक आपदा का दंश झेल रहा है।12 अप्रैल से 03 जून 2020 के बीच 9 बार भूकंप के झटकों ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की धरती को दहला दिया था।एक साथ इतने कम अंतराल में भूकंप के झटकों का आना मानव अस्तित्व और पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत नहीं है।अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान आया था।20 मई 2020 को भारत में चक्रवाती तूफान अम्फान ने सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ढाया।चक्रवाती तूफान अम्फान से जो तबाही हुई उससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों का घर उजड़ गया है और लोगों की जाने भी गई ।पड़ोसी देश बांग्ला देश भी अम्फान तूफान का शिकार हुआ।अम्फान तूफान के बाद 3 जून 2020 को महातूफान निसर्ग 120 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के तटीय क्षत्रों से टकराया। 120 वर्ष के बाद इस तरह की कोई स्थिति महाराष्ट्र में आई । इस तूफान ने रत्नागिरी जिले में तबाही मचाई अरब सागर में उठा निसर्ग चक्रवाती तूफान ने सबसे ज्यादा कहर रत्नागिरी में ढाया।निसर्ग बंगाली का शब्द है जिसका मतलब श्प्रकृतिश्होता है। समुद्री तूफानों के नाम की जो नई लिस्ट तैयार हुई है,उसमें निसर्ग पहला नाम है। वर्ष 2020 में जैविक आपदा और प्राकृतिक आपदाओं का कहर ये साबित करता है की मानव ने काफी लम्बे समय से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है।वर्ष 2020 में पूरा विश्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से सहमा हुआ है। इन आपदाओं ने मानव अस्तित्व पर गहरी चोट दी है।आपदाओं से बचने के लिए हमे अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना होगा । अतएव हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति की गोद में पलटा -बढ़ता है।

न्यूज ब्रीफ

बुरहानपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रेक्टर-ट्राली से तिपहियां स्कूटर भिड़ा

हादसे में जीजा की मौत साला गंभीर

माही की गूंज, बुरहानपुर।

बुरहानपुर जिले में खकनार थाना अंतर्गत सोमवार देर रात भारी बारिश के बीच बुरहानपुर- अमरावती मार्ग पर ग्राम तलावड़ी के पास सड़क किनारे अंधेरे में खड़े ट्रेक्टर-ट्राली से तिपहियां स्कूटर जा भिड़ा। जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर हुए हादसे में स्कूटर चालक जीजा की मौत हो गई और पीछे बैठा साला गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक दिव्यांग है और अपने साले को छोड़ने उसके गांव जा रहा था। घायल युवक का शासकीय जिला चिकित्यालय में उपचार चल रहा है। जांचकर्ता सहायक उपनिरीक्षक शंकरलाल लोणे ने बताया कि हादसे में सुभाष भील 37 निवासी ग्राम सीतापुर थाना शाहपुर की मौत हुई है और पंकज तडोले 33 निवासी ग्राम ताजनपुर घायल हुआ है।

24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले, 2 की मौत

माही की गूंज, बुरहानपुर।

बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 9 नए मामले आए है तो उपचार के दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विक्रमसिंह वर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह आई रिपोर्ट में 3 नए मामले आए है। इनमें 2 पुरूष और एक महिला है। यह नए मरीज सुदामा नगर, सलीम नगर व ग्राम महलगुराड़ा के है। जबकि बीते 24 घंटे में 9 नए मामले आए है। इससे बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 394 मरीज हो गए है। गत 24 घंटे में उपचार के दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यह लोग ग्राम लोणी व लोधीपुरा के है। बुरहानपुर में अभी तक कोरोना से 22 लोगों की मौत हुई है। इनमें 8 महिलाएं है।

पूर्व विधायक का परिवार भी कोरोना की चपेट में

माही की गूंज, बुरहानपुर।

बुरहानपुर में चीनी वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है। बुरहानपुर में फैले संक्रमण की चपेट में पूर्व विधायक का परिवार भी आ गया है। कल आई रिपोर्ट में राजपुरा में रह रहे इस परिवार की बड़ी पुत्रवधु कोरोना संक्रमित पाई गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विक्रमसिंह वर्मा ने बताया कि इस परिवार की 73 वर्ष की महिला के कोरोना संक्रमित होने पर उसे उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राजपुरा चौराहा पर स्थित मकान को चारों और से सील कर संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है।

युवती ने की आत्महत्या

माही की गूंज, बुरहानपुर।

बुरहानपुर जिले में लालबाग थाना अंतर्गत ग्राम बहादरपुर में सोमवार को नवयुवती ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बहादरपुर में वंसुधरा चौधरी 17 ने घर में कीटनाशक पी लिया था। मृतिका स्थानीय शासकीय शाला में कक्षा 10 वीं की छात्रा थी। घटना के समय परिजन खेत पर गए थे और नवयुवती घर पर अकेली थी। शासकीय जिला चिकित्यालय के पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक रंजीतसिंह यादव ने बताया कि परिजन उसे मृत अवस्था में उपचार के लिए चिकित्यालय लाए थे।

खेती में नित नए नवाचार कर रहे है किसान, मिल रहा फायदा

खेती में इस तकनीक के प्रयोग से बढ़ रही युवा किसान की आमदनी

माही की गूंज, सनावद।

क्षेत्र में किसान अब जागरूक हो गये हैं। खेती में नित-नये नवाचार कर रहे हैं। पारम्परिक खेती छोड़ी नहीं हैं लेकिन केवल उसी के भरोसे भी नहीं हैं। अब किसान ड्रिप मल्चिंग प्रयोग बेहिचक कर रहे हैं। कृषि में नवाचारों का प्रयोग करके की जा रही खेतीबाड़ी किसानों की तकदीर बदल रही है। नए नए नवाचारों का प्रयोग करके काफी किसान न अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं बल्कि पानी की बचत करने के साथ ही खेत में अनुपयोगी खरपतवार से भी निजात पा रहे हैं। खेती की एक तकनीक का नाम है मल्चिंग। मल्चिंग से किसान न केवल परंपरागत खेती से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं बल्कि कम पानी के इस्तेमाल से अच्छी खेती कर रहे हैं। क्षेत्र में कई किसान खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं ग्राम ढकलगांव के एक युवा किसान मल्चिंग के जरिए मिर्च की खेती करके अच्छा उत्पादन करते है।आपको बता दें कि परंपरागत फसलों के मुकाबले बागवानी व सब्जी वाली फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देने वाली साबित होती आई हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत, जोखिम उठाना और सही जानकारियाँ मिलना काफी जरूरी होता है लेकिन काफी बार किसान नवाचार की जानकारी के अभाव में मजबूरन पुराने तरीके से ही खेती करते हैं। इसके विपरीत जो किसान हिम्मत करके नवाचारों से खेती करते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है।वहीं ग्राम ढकलगांव के युवा किसान राजेश सालीया ने कुछ ऐसी ही हिम्मत दिखाई। युवा किसान राजेश सालीया ने ठान लिया कि एक बार नवाचार का प्रयोग कर खेती करेंगे। उन्होंने अपनी ही सलाह से मिर्च की खेती करने का फैसला किया।चार माह पूर्व राजेश सालीया ने अपने एक बीघा खेत को मिर्च की खेती के लिए चुना। युवा किसान राजेश सालीया ने खेत की तैयारी की। उर्वरकों और कीटनाशकों के इंतजाम किए। सिंचाई की व्यवस्था की। ज्यादा पैदावार लेने के लिए उन्होंने ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की और खेती के लिए मल्चिंग पद्धति का सहारा लिया। जिसके चलते युवा किसान को 1 लाख की मिर्च की फसल ली थी। वहीं बागवानी भी लगाई जिसमें 80 हजार रूपये का मुनाफा मिला। अभी युवा किसान राजेश सालीया ने 4 एकड़ जमीन किराए की ली है। किराए से ली जमीन को भी अब ड्रिप मल्चिंग के जरिए मिर्च की खेती करके अच्छा उत्पादन करने की आश में है।

क्या है ड्रिप मल्चिंग का तरीका

युवा किसान राजेश सालीया ने इस सिस्टम में खेत को प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है, जिसे खेत में नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं पनप पाते हैं। प्लास्टिक की शीट अलग अलग साइज में मिल जाती हैं। इन शीटों के बीच में तयशुदा दूरी पर छेद करके मिर्ची का पौधों का रोपण किया हैं। ड्रिप के जरिए रासायनिक खादें भी दी जा सकती है। ड्रिप सिस्टम से सिंचाई से न केवल पानी की बचत होती बल्कि कम पानी की उपलब्धता के बावजूद ड्रिप इरीगेशन से किसान अच्छी सिंचाई कर रहा हैं। इस तकनीक से खरपतवार पर रोकथाम, पानी की बचत तथा समय और श्रम बचता है।

प्लास्टिक मल्चिंग के फायदे

मल्चिंग के उपयोग से खरपतवारों को उगने से रोका जा सकता है, इससे पानी की बचत होती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रित होने के कारण पौधों के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनता है और जड़ों का बेहतर विकास होता है। जमीन को कठोर होने से बचाया जा सकता है। यही नहीं बीज का जल्द अंकुरण और उपज बढ़ाने में भी प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक की अहम भूमिका होती है।इससे खेत में नमी बनी रहती है और मिट्टी से होने वाला वाष्पीकरण भी रुक जाता जाता है।

अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर छाई खुशी, मिर्ची की बोवनी शुरू।

रविवार को हुई बारिश से मिली राहत

ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार रात में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे जहां खिल उठे। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली। झमाझम बारिश के बाद खेतों में किसानों की चहलकदमी बढ़ गई। मिट्टी में नमी के बाद किसान बोवनी मे जुटे। कपास, मिर्ची आदि की बुवाई व रोपनी शुरू की। किसानों की माने तो इस साल मौसम मेहरबान है। ऐसा ही मौसम मेहरबान है। ऐसा ही मौसम रहा तो इस बार उपज अच्छी मिलेगी। शुरूआत अच्छी हुई है। समीपस्थ ग्राम बोरूट के किसान यशवंत पटेल, दिनेश वासिया, संदीप सेजगांया, सुखदेव पटेल, राजेश पटेल, लवकुश ने बताया कि अभी थोड़ा और बारिश अच्छी होती है तो जो बुआई व रोपाई के लिए अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि आगामी 2 से 3 दिन लगातार बारिश होने के आसार है। इसलिए खेंतो मे मिर्ची के रोपे भी लगाए जा रहे है।

सुरतीपुरा तालाब का हो गहरीकरण

माही की गूंज, बड़वाह।

नगर से लगभग तीन किलोमीटर दूर पूर्व में घने जंगलों के बीच बने सुरतीपुरा तालाब प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। जहाँ पर प्राचीन नागमन्दिर है जो श्रद्धालुओ के लिए आस्था का प्रतीक है ।वहा से कुछ ही दूरी पर डॉलारी आश्रम है आये दिन तीज त्योहारों पर श्रद्धालुओ की भीड़ लगी रहती है।इसी बीच रास्ते मे सुरतीपुरा तालाब है गर्मी के दिनों में यह तालाब पानी विहीन हो जाता है ,जंगली जानवरों व पशु पक्षियों को पीने का पानी नही मिल पाता है जिससे प्रतिवर्ष कहि प्यासे ही मर जाते है और यह अखबारों की सुर्खियों में समाहित हो जाते है ।लेकिन शासन-प्रशासन इस और कोई ध्यान नही देता।जबकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ,यदि तालाब का गहरीकरण होता है ,तो एक तो जल संकट दूर होने से जंगली जानवर पशु पक्षी भी नही मरेंगे,साथ ही तालाब में यदि पानी रहेगा तो उससे जुड़े नदी नालों व खेत मे खुदे कुओं का जलस्तर भी सुधरेगा और वन क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी ।कुछेक लोगो से जानकारी लेने से ज्ञात हुआ है कि वन क्षेत्र होने से तालाब का गहरीकरण नही करवाया जाता, यदि ऐसा है तो वन विभाग ने इसकी अनुमति देनी चाहिए क्योंकि गहरीकरण करने से अनेको जनहितैषी के कार्य संपन्न होंगे व सेकड़ो वन्यप्राणियो के जान की रक्षा भी होगी ।शासन इसके लिए ठोस नीति बनाये जिससे खत्म होते तालाब का पुनः उद्धार हो सके ! -एन.एस.सोलंकी संयोजक -सामाजिक विचार मंच बड़वाह।

आधार सीडिंग से शेष रहे हितग्राही शीघ्र ही कराए अपना आधार सीडिंग

माही की गूंज, बड़वानी। जिला आपूर्ति अधिकारी बीके कोष्ठा ने लक्षित सार्वजनित वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे ऐसे हितग्राही जिनके परिवार व सदस्यों के आधार नम्बरों की अभी डाटाबेस में प्रविष्ठी नहीं हुई है। उन्हें शीघ्र ही अपने उचित मूल्य की दुकानों पर आधार नम्बर सहित उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर सीडिंग करवाने का अनुरोध किया है। जिससे भविष्य में उन्हें राशन नहीं मिलने की परेशानियों से गुजरना ना पड़े।

1 से 9 जुलाई तक पंचायतों में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे

माही की गूंज, खरगोन। त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता का आमजनों के निरीक्षण के लिए समस्त पंचायतों में 1 जुलाई को सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौरान जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ऐसे युवक व युवति के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं जिन युवतियों के विवाह होकर अन्यत्र स्थानों पर चली गई हो तथा मृतक हो चुके महिला व पुरूष के नाम भी मतदाता सूची में से हटाने एवं संशोधित करने की कार्यवाही की जाएगी। सीईओ शर्मा ने कहा कि समस्त पंचायतों में यह कार्यवाही 9 जुलाई तक की जाएगी।

किसान भाई तत्काल पूर्ण करें बोवनी का कार्य - डीडीए खपेड़िया

माही की गूंज, बड़वानी।

उपसंचालक कृषि केएस खपेड़िया ने किसान भाईयों को सलाह दी है कि सम्पूर्ण जिले में लगभग 5 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। अतः वे तत्काल बोवनी का कार्य पूर्ण करें, जिससे लगाए गए बीज में अच्छा अंकुरण हो सके।

खपेड़िया ने किसान भाईयों को सलाह दी है कि वे प्रमाणित बीज ही बोवनी के काम में लाए। अगर प्रमाणित बीज उपलब्ध न हो तो स्वयं का बीज बोने के लिए उपयोग करें। किन्तु ध्यान रखे कि बीज की अच्छी तरह से ग्रेडिंग व सफाई कर लें, वही बाविष्टिन या ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित कर ही बोये । इसके लिये किसान भाई इन दवाईयों के 3 ग्राम की मात्रा लेकर उसे प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करें । इसके साथ ही उन्होने किसानो को सलाह दी है कि बीज लगाने के पूर्व उसके अंकुरण क्षमता भी ज्ञात करना आवश्यक है। इसके लिये किसान बन्धु बीज का 100 दाना ले और उसे मिट्टी में नम कर बुवाई करे । जब तक अंकुरण नहीं हो जाता, तब तक मिट्टी में नमी बनी रहना चाहिए। लगभग 6 से 7 दिन पश्चात अंकुरण होकर पौध जमीन के ऊपर दिखने लगे, उस समय पौधा की गिनती करें, यदि 100 बीजों में 60 से 70 बीज अंकुरित होते हैं तो मान ले कि उक्त बीज बुवाई के लिए अनुकूल है।

उन्होने किसानों को सलाह दी है कि वे निजी विक्रेताओं से बीज लेते समय पक्का बिल प्राप्त करें। वहीं बीटी कपास के चारों ओर नान बीटी कपास की 4 - 4 कतारे अवश्य लगाये। जिससे बीटी कपास में कीड़े एवं बिमारियॉ नही लगने पाये । साथ ही उन्होने किसान भाईयों को अंतरवर्तिय फसल जैसे - सोयाबीन के साथ मक्का, सोयाबीन के साथ अरहर, कपास के साथ मक्का, मुंगफली के साथ अरहर बोने की भी सलाह दी है जिससे यदि किसी कारणवंश एक फसल प्रभावित होती है तो दूसरी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके ।

निजी प्रतिष्ठानों का जारी है निरीक्षण

उपसंचालक कृषि श्री खपेडिया ने बताया कि किसान भाईयों को प्रमाणित खाद - बीज - दवाईयॉ मिल सके, इसके लिये कृषि विभाग का अमला सतत निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। यदि किसी किसान को बीज प्राप्त करने या पक्का बिल नही मिलने की कोई समस्या है तो वह तत्काल अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें, जिससे दोषी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कठौर कार्यवाही की जा सके।

कैंसर से बिखरे परिवारों को शासन के संबल से मिला सहारा

देवकांत पंड्या अपने घर व बेटी के साथ।

आशा राठौर अपने घर व बेटियों के साथ।

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन के दो परिवारों की दास्तानें एक जैसी लगती है। दोनों ही परिवारों में कैंसर ने अपनी जगह बनाई और परिवारों को बिखेरकर रख दिया। कैंसर से उभरने के लिए दोनों ही परिवारों ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। जब उपचार के लिए रूपए नहीं थे, तो किसी ने अपना आशियाना ही गिरवी रख दिया। जबकि एक परिवार ने अपने रिश्तेदारों और मिलनसार लोगों से कर्ज लेकर कैंसर से मुक्ति के बड़े जतन किए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही परिवारों में आखिरकार अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। खरगोन के धोकपुरा निवासी देवकांत पंड्या जिनकी पत्नी सिंधु पंड्या करीब 2 वर्ष तक कैंसर से जुझती रहीं। पति देवकांत ने उनके उपचार के हर संभव प्रयास किए। उपचार के लिए मकान तक गिरवी रखा। वे उनकी धर्मपत्नी का इंदौर के ग्रेटर कैलाश अस्पताल में उपचार कराते रहे। मजदूरी करने वाले देवकांत ने फिर भी हार नहीं मानी और निरंतर डेढ़ वर्ष तक उपचार कराया। आखिरकार डॉक्टरों ने भी उपचार के बाद घर पर पूरा आराम करने की सलाह दी। नवंबर 2019 में सिंधु पंड्या का देहांत हो गया। सिंधु अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़कर गई। देवकांत पर अब 22 वर्षीय शक्ति, 19 वर्षीय चंद्रकांता, 16 वर्षीय रानी, 12 वर्षीय युवराज और 6 वर्षीय कल्याणी की जिम्मेदारी है। ऐसे समय में मप्र शासन की संबल योजना के तहत देवकांत को 2 लाख रूपए मिले, जिससे वे अपने चार बच्चों को पढ़ाई में खर्च करना चाहते है, जबकि छोटी बेटी कल्याणी को अपने बड़े भाई को गोद दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से घर की चिंता से मुक्ति

ऐसा ही कुछ गांधी नगर के राठौर परिवार में भी आफत आ खड़ी हुई। यहां 55 वर्षीय विरेंद्र राठौर जो अपनी रोजी-रोटी बस स्टैंड पर गाड़ियां धोकर चलाते थे। उन्हें 2 वर्ष पहले डॉक्टरों ने कैंसर की समस्या बताई। पत्नी आशा राठौर पर जैसे दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और इंदौर के एमव्हाय अस्पताल के अलावा अरविंदों अस्पताल और बड़ौदा तक के अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन किस्मत के आगे किसका बस चलता है? अक्टूबर 2019 में विरेंद्र पत्नी और अपनी दो लड़कियों को छोड़कर इस दुनियां से चले गए। पत्नी आशा राठौर मास्टर कॉलोनी के शासकीय स्कूल में मध्यान्ह भोजन बनाने के बाद कॉलोनियों के 3-4 घरों में खाना बनाकर अपना घर चलाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों की पढ़ाई जारी रखीं। आज उनकी लड़कियां खरगोन महाविद्यालय से बीएससी कर रही है। ऐसे समय में शासन की संबल योजना से बहुत बड़ा सहारा मिला है। आशा बताती है कि उनके उपचार के लिए जो कुछ कर्ज लिया था, उसे पूरा करेगी और बचा रूपए बच्चों की पढ़ाई के उपयोग में लाएगी। भला हो भारत सरकार का, जिससे हमारे आशियाने की चिंता दूर हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा घर बन गया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

डीडी भारती से योगाभ्यास का हर दिन हो रहा है प्रसारण

माही की गूंज, बड़वानी। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर डीडी भारती पर सामान्य योगाभ्यास (कॉमन योगा प्रोटोकॉल-सीव्हायपी) का प्रसारण किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के सहयोग से प्रसारित यह योगाभ्यास हर दिन सुबह 8 से 8.30 बजे तक देखा जा सकता है। यह मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक साथ उपलब्ध होंगे।

नेहरू युवा केन्द्र बड़वानी के जिला समन्वयक श्री नितेश सोनी ने बताया कि आधे घंटे के इस सत्र में सामान्य योग अभ्यासक्रम के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है। सामान्य योग अभ्यासक्रम से पहले से अवगत हो जाने से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में सक्रिय भागीदारी के लिए पूरी तरह से तैयार होने में मदद मिलेगी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोविड - 19 के कारण स्वास्थ्य आपातकाल के हालात के बीच आया है। इस स्थिति में योग विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस वर्ष इन विशेष परिस्थितियों में यह अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वर्ष के योग दिवस यानी 21 जून 2020 को घर पर योग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है - " घर पर योग और परिवार के साथ योग "

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व सामान्य योग अभ्यासक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सामान्य योग अभ्यासक्रम को प्रमुख योग गुरुओं और विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया है और इसमें लोगों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित अभ्यास शामिल किए गए हैं। यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय योग कार्यक्रमों में से एक है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसका व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि किसी भी आयु का व्यक्ति, चाहे कोई महिला हो या पुरुष, इसे आसानी से अपना सकता है और इसे सरल सत्रों और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सीखा जा सकता है।

सांची की थैलियों में आ रहा दूध कुछ ही घंटे में फटने से ग्राहक हो रहे परेशान

ग्राहक बोले घटिया क्वालिटि का दूध हो रहा सप्लाई

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला मुख्यालय सांची का दूध खरीदने के कुछ घंटे बाद ही सांची का दूध फट रहा है, जिससे मुख्यालय ही सांची के दूध की दुर्दशा है तो जिले के अन्य जगहो पर सप्लाई हो रहे दूध की क्या हाल हो रहे होगे यह भगवान ही जाने.? ग्राहक तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि घटिया क्वालिटी का दूध सप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण हमारे पैसों की बर्बादी हो रही है। यह हम नहीं सांची का दूध खरीदने वाले ग्राहक कह रहे हैं। ग्राहकों ने तो यहां तक कहा है कि समय रहते सांची प्लांट के जिम्मेदार बेहतर माल ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ग्राहक दूसरी कंपनी के दूध लेने पर विवश हो जाएंगे जिसका खामियाजा सांची को भुगतना पड़ेगा। सांची ग्राहकों को गुणवत्ता वहींन दूध देने के कारण ग्राहक अब उपभोक्ता फोरम जाने की बात कर रहे हैं। वहीं एक तरफ लॉकडाउन में हर वर्ग का व्यक्ति पैसे की तंगी से होकर गुजर रहा है वही सांची का दूध खरीदने वाले ग्राहक पैसा लगाने की बावजूद कुछ समय बाद दूध फटने के कारण उनका पैसा बर्बाद हो रहा है वही ग्राहक दूध फटने के कारण पैसा बर्बाद हो रहा है इसके कारण वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कुछ ग्राहकों ने तो सांची के दूध फटने के कारण अमूल का दूध लेने पर विवश हो गए हैं। वही सांची प्रबंधक गुप्ता यहां तक कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर की लापरवाही के कारण व लोग ज्यादा समय तक दूध को बाहर रखते हैं जिसके कारण दूध फट रहा होगा। प्रबंधक ने यहां तक कहा कि किसी डीलर का दूध फट जाता है तो हम बदल भी देते हैं लेकिन हमने पूछा कि वर्तमान समय में किस का बदला तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इससे साफहै कि अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर इस जगह पर काम हो रहा है। इससे साफहै कि इसकी टोपी उसके सर रख कर के अपना पल्ला झाड़ने में जिम्मेदार लगे हुए हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर अपने खुद की ग्राहकी पर कुल्हाड़ी मार रहा है.? या जिम्मेदार गुप्ता सांची डिस्ट्रीब्यूटर नाम बता कर के अपनी ओर से पल्ला झाड़ रहा है गुप्ता की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि गलती अपने प्लांट से हो रही है और दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं एक कहावत भी चरितार्थ यहां साफदिखाई देती है गुप्ता का इशारा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज कहावत चरितार्थ होकर साफनजर आ रही है।

सप्ताह भर से आ रही शिकायतें

हर रोज ग्राहकों की सांची दूध फटने की शिकायतें आ रही है। सांची पॉइंट पर ग्राहकों द्वारा जो दूध खरीदा जा रहा है खरीदने की कुछ घंटे बाद ही अचानक फट जाता है ऐसा मुख्यालय के सांची के अधिकांश पॉइंटो पर दूध फटने समाचार मिल रहे हैं। दबी जुबान में पॉइंट विक्रेताओं का कहना है कि जिम्मेदारों को अवगत करवाने के बावजूद भी वह हमारी एक नहीं सुनते, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस तर्ज पर हम लोगों को धमकाया जाता है इसके लिए हम उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते, जिम्मेदार यहां तक कहते हैं कि यदि आप लोगों ने हमारी शिकायत की तो हम आपको सांची पॉइंट से बेदखल कर देंगे और दूसरे को यह पॉइंट अलाट कर देंगे इसके लिए पॉइंट विक्रेता भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है जबकि पॉइंट विक्रेता जानता है कि आज की तारीख में जो सांची का दूध आ रहा है जिसका मेंटेनेंस सही नहीं होने के कारण लेने के कुछ घंटे बाद ही फट जाता है इनकी शिकायतें पॉइंट पर पर ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। पॉइंट विक्रेता कह रहा मुझे भी ग्राहक हर रोज आकर के दूध फटने की ग्राहक सूचना दे रहे हैं लेकिन मैंने जिम्मेदारों को अवगत करवा दिया तभी वह मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। सांची का दूध फटने के कारण सांची दूध खरीदने वाले ग्राहक भी अब प्राइवेट कंपनी का दूध खरीद रहे हैं जिससे उनकी ग्राहकी भी प्रभावित हुई है लेकिन जिम्मेदार है कि क्वालिटी को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहे हैं।

ग्राहको का कहना

सांची दूध लेने के दो-तीन घंटे बाद ही दूध फट जाता है मैंने इंदौर भी शिकायत की है। जिसके कारण मेरा नुकसान हो रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं उपभोक्ता फोरम में जाने की तैयारी कर रही हूं।

श्रीमती संगीता वाजपेई, गृहणी

दो-चार दिन से हमें भी ग्राहकों द्वारा शिकायतें मिल रही है मैंने जिम्मेदारों को अवगत करवा दिया गया है लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला।

विजय वाखला,सॉची पाइंट विक्रेता

जिम्मेदारो का कहना-

प्रबंधक ने माना कि शिकायतें मिल रही है ज्यादा समय तक डिस्ट्रीब्यूटर दूध को बाहर रखते हैं उनकी लापरवाही के कारण दूध फट जाता है।

एलएन गुप्ता , सांची दूध संयत्र, प्रबंधक झाबुआ

पुलिस ने आठ गाय से भरी पिकअप के साथ दो तस्करों को पकड़ा

माही की गूंज, पंधाना (खंडवा)।

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव पुलिस ने आठ गाय से भरी पिकअप के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सोमवार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप क्रं.एमपी 42 जी 3571 मे महाराष्ट्र कत्लखाने के लिए गाय की तस्करी हो रही है। चौकी प्रभारी जगदीशसिंग सिंधिया ने बल के साथ हाईवे स्थित मां बागेश्वरी मंदिर के सपीप सुक्ता पुल पर नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू की। इस दौरान जब पिकअप को बाहर से देखा तो तस्करों ने अंदर आठ गाय के पैर व मुंह को बुरी तरह रस्सी से बांध ठूंस-ठूंसकर भरा था। और अंदर बंद गाय के उपर गुमराह करने के लिए लसन का भूसा भर रखा था। पुलिस ने पिकअप में सवार आरोपी मोहित पिता कैलाश (19) निवासी अलीसरखेड़ा, जिला शाजापुर व गोपाल पिता पप्पू (20) निवासी बावलदा जिला राजगढ़ को पकड़ा। इस संबंध में चौकी प्रभारी जगदीशसिंह सिंधिया ने बताया कि पिकअप से जप्त गाय को गौशाला भेज दिया गया है और दोनों आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।

अवैध फालिया लेकर दहशत फैलाने वाले को न्यायालय ने भेजा जेल

माही की गूंज, थांदला। न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जय पाटीदार ने अवैध फालिया लेकर आम जनता को भयभीत करने वाले आरोपी को जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि एक व्यक्ति बस स्टैंड सुतरेटी रोड पर मेरे खेत पर हल किसने चलाया, मैं उसको मार डालूंगा चिल्ला रहा था और लोहे का फालिया लेकर उल्टा सीधा घुमा रहा था। जिससे आम जनता भयभीत हो रही थी। थांदला पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और उसके हाथ में लिए लोहे के फालिया को जप्त कर आरोपी से लाइसेंस मांगा। लाइसेंस नहीं होने पर मौके पर फालिया जप्त कर आरोपी संजू पिता पालजी मावी निवासी खजूरी फलिया नौगांवा को गिरफ्तार किया। थाना थांदला पर आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आज न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - कलेक्टर सिपाहा

माही की गूंज, झाबुआ। जिला जल तथा स्वच्छता मिशन की बैठक मंगलवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर तथा अध्यक्ष प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता का जल प्रदाय करना है। बैठक में बताया गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 375 पंचायतों, 781 ग्रामों में 4 हजार 931 बसाहट है। जिले में 80 नल जल योजना स्थापित है। जिसमें लगभग 26 हजार घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध है।

कलेक्टर सिपाहा ने अवगत कराया कि इस मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में पूर्व से स्थापित नल-जल योजनाओं का रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत जन समुदाय सहयोग लिया जाएगा। सामान्य श्रेणी बाहुल्य ग्रामों मे योजना की लागत का 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति, बाहुल्य ग्रामों में योजना की लागत का 5 प्रतिशत तथा पहाड़ी व वन क्षेत्र योजना की लागत का 5 प्रतिशत, जन सहयोग, नगदी, सामग्री, श्रम के रूप में लिया जा सकता है। इस बैठक में जल जीवन मिशन की अवधारणा पर विस्तार से जानकारी दी गई। एकल ग्राम योजना के अंतर्गत उचित गुणवत्ता का पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले ग्राम का चयन करने, गुणवत्ता प्रभावित पर्याप्त जल स्तर वाले ग्राम का चयन करने सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिये प्रथम बसाहटों का चयन करने तथा समूह ग्राम योजना के अंतर्गत जल एकत्रीकरण वितरण प्रणाली, समूह क्षेत्रीय नल जल योजना के लिये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। सिपाहा ने निर्देश दिए हैं कि इस जल मिशन के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना तैयार करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति का गठन की कार्यवाही शीघ्र की जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के जलासयों में पानी की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की और जिला अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जल जीवन मिशन का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर जन जागरूकता लाने के लिए भी कहा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा सदस्य सचिव एनएस भिड़े, परियोजना प्रशासक आईटीडीपी प्रशांत आर्य, उपसंचालक कृषि एनएस रावत, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन प्रवीण कुमार खरत जिला सलाहकार धूलिया बामनिया, सहायक यंत्री राहुल सूर्यवंशी, शैलेश बघेल, गंगासिंह रावत तथा समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

स्वास्थ्य विभाग की अपील, बाहर से आने वाले लोग खुद ही आकर कराएं जांच

माही की गूंज, झाबुआ।

कोरोना संक्रमण काल में जहां इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दिन रात एक कर कार्य किए जा रहे है। वहीं इसके विपरित झाबुआ जिले में बाहरी लोगों का आना-जाना कम नहीं हो पा रहा है। वहीं कई लोग तो गुजरात, राजस्थान तथा मप्र के इन्दौर जैसे ईलाकों से झाबुआ जिले सहित नगर में आ रहे है। जहा वर्तमान में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज है। बावजूद इसके लोगों के द्वारा जागरूकता की कमी के कारण कही कोरोना संक्रमण की बाढ़ ना आ जाए। वहीं मरिजों की संख्या में ईजाफा ना हो जाए।

जिले में पूर्व में पेटलवाद क्षेत्र के ग्राम नाहरपुरा की महिला को कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुई थी। जिस पर से उसका ईलाज जिला चिकित्सालय में पूर्ण होकर वो स्वास्थ्य हुई और आज अपने घर पर है। वहीं इसके बाद जिला चिकित्सालय के ही शासकीय वाहन चालक हुसैन अली को कोरोना पॉजिटिव निकला था जिसके बाद से उनके परिवार के करीब 6 लोागों को कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसमें हुसैन अली की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद से तीन और लोगों को कोारोना संक्रमण पॉजिटिव निकला था जिस पर से उन्हे कोरोना सेन्टर पर ईलाज के लिए भेजा गया था और वे ठिक होकर अपने घर लौट चुके है। विगत दिनो में सुभाष मार्ग मे एक व्यक्ति को इंदौर ईलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकला। जिस पर से नगर के मध्य स्थित सुभाष मार्ग को पूर्णतः सील कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। उनके भी पुरे परिवार की जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी झाबुआ जिले में बरकरार है। बावजूद इसके झाबुआ जिले में बाहरी लोगों का आना-जाना चलता रहेगा। तब तक कोरोना का खतरा कम नहीं होगा।

जिला प्रशासन को करना होगा इंतजाम

कोरोना संक्रमण के शुरूआत से पहले ही जिला प्रशासन सतंर्क हो चुका था। जिस पर से पुरे झाबुआ जिले को लॉकडाउन का पालन करने के लिए आदेश भी दिए गए। वहीं इस आदेश के तहत ही संपूर्ण जिला आज कोरोना संकट से मुक्त हो पाया है, लेकिन आज भी बाहरी लोगों की आवाजाही से कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बाहरी लोगों के आने-जाने पर उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, जिससे की यह पुष्टि हो जाए कि वे संक्रमित नहीं है। जिले की सभी सीमाओं को भी एक बार फिर से सील कर वहां पर सख्ती से पालन करवाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में सीमाओं से सील हटाने के बाद लोगों का बेधड़क आना-जाना चल रहा है। ऐसे में कही कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि किसी के भी संपर्क में आया तो पूरे झाबुआ जिले को संक्रमित कर देगा। इसके लिए जिला प्रशासन को चाहे वो माछलिया घाट, पिटोल बार्डर हो, चाहे थांदला की बार्डर हो सख्ती से आने-जाने वालों की पहले जांच करे उसके बाद ही उन्हे आने या जाने दिया जाए। यदि बाहरी लोगों का आना-जाना इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना संक्रमण से पुरा झाबुआ जिला लाचार हो जाएगा। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की दरकार है।

सुभाष मार्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

कोरोना वायरस को लेकर नगर के वर्तमान मे कंटेटेमन्ट एरिया सुभाष मार्ग मे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लोगो की स्क्रेनिंग कर उनकी जांच की गई। वहीं विभाग के कर्मचारियों के द्वारा चांच मे उपयोग होने वाली पुरी पीपीटी कीट पहनकर लोगों के घरों तक जा जाकर उनकी सेम्पलिंग ली गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम हरसंभव प्रयासरत है। वहीं उनके द्वारा नगर की जनता से अपील की जा रही है कि कंटेटमेन्ट एरिया में ना जाए और वहां रहने वालों का हौसला बढ़ाए। वहीं इस क्षेत्र के लोग भी अभी कुछ दिनों के लिए अपने घरों में रहे ताकि संक्रमण के इस खतरे को यही रोका जा सके। जिससे की झाबुआ जिला ग्रीना झोन में ही बना रहे। वहीं कोरोना संक्रमण कोविड-19 में इस समय अपनी पुरे समय सेवाएं दे रहे जिला चिकित्सालय के आरएमओ डॉ. सावनसिंह चौहान का कहना है कि यदि नगर या जिले में कही भी किसी भी क्षेत्र में यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आप खुद आकर अपनी कोरोना की जांच करवाए। ताकि यदि आपको कोई संक्रमण होगा तो कम से कम वह दूसरों को तो नहीं फैलेगा। यदि इस संबंध में आप स्वास्थ्य विभाग से छुपाएंगे तो हो सकता है कि वो संक्रमण आपके घर तक पहुंच जाए जहां आपका पुरा परिवार है जहां आपके घर में औरतें तथा छोटे-छोटे बच्चे है जिनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के अनुसार बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच करवाना जरूरी है। जिससे की आप और आपका परिवार स्वस्थ्य रह सके।

बद्रीलाल नीमा का देवलोकगमन

माही की गूंज, झाबुआ। फोटोग्राफर एसोसिएश के अध्यक्ष दीपक नीमा व ज्योति स्टुडियो संचालक के पिताजी बद्रीलालजी नीमा का रविवार को देवलोकगमन हुआ। जिस पर से पूरे नगर में शोक की लहर छा गई। वहीं उनकी अंतिम यात्रा उनके निज निवास स्थान अम्बे माता मंदिर के पास पिली कोठी के सामने से शाम 4.30 बजे निकाली गई। शासन के निर्देशानुसार सीमित संख्या, सोश्यल डिस्टेसिंग तथा मुंह पर मास्क लगाकर ही नगर के नागरिक नीमा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अंतिम संस्कार माधोपुरा मुक्ति धाम पुलिस लाईन के पिछे किया गया। वही मुखाग्नि उनके बेटे दीपक नीम द्वारा दी गई।

चंद्रसेन संघवी का हुआ देवलोकगन

माही की गूंज, झाबुआ। हस्तीमल, इंद्रसेन, लोकेंद्र, धनसुख, दिलीप संघवी के बड़े भ्राता, नीरज संघवी के पिताजी तथा प्रवीण, सुमित, जयेश, सौरभ, धर्मेंद्र, पवन, दर्शन के बड़े पापा चंद्रसेन सागरमल संघवी' का संथारा पूर्वक देवलोक गमन मंगलवार हो गया है। इनका अंतिम संस्कार गेल मुक्तिधाम पर किया गया। वहीं मुखग्नि नीरज संघवी ने दी।

कोरोना काल में स्वच्छता टीम कर रही सराहनीय कार्य

पूरे शहर को सेनेटाईज करने के साथ ही सफाई व्यवस्था को रखा जा रहा चुस्त-दुरस्त

माही की गूंज, झाबुआ।

नोवेल कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु झाबुआ शहर में जब से लॉकडाउन लगा है, तब से शहर में स्वच्छता के मामले में नगरपालिका परिषद् की स्वच्छता शाखा ने एक अलग ही किर्तिमान हासिल किया है। कोरोना काल में पूरे शहर को सेनेटाईज करने के साथ सफाई के मामले में भी नगरपालिका अव्वल रही है।

नगरपालिका परिषद् झाबुआ की अध्यक्ष मन्नूबेन डोडियार तथा सीएमओ एलएस डोडिया के मार्गदर्शन में नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी यूनूसुउद्दीन कुरैशी, सेनेट्री प्रभारी कमलेश जासयसवाल तथा सहायक स्वच्छता निरीक्षक टोनी मलिया के नेतृत्व में स्वच्छता शाखा द्वारा दिन-रात शहर में स्वच्छता मुहीम संचालित की जा रहीं है। नपा के सेनेट्री प्रभारी जायसवाल ने बताया कि झाबुआ शहर में गत 21 मार्च से लॉकडाउन लगा है। तब से लेकर आज तक भी स्वच्छता शाखा की ओर से संपूर्ण शहर में सेनेटाईज का कार्य जारी है। नगरपालिका के सफाईकर्मी कोरोना यौद्धा के रूप में गली-मौहल्लों और कॉलोनियों में घर-घर, दुकान-दुकान जाकर सेनेटाईज करने के साथ मुख्य बाजारों में भी नपा ने टेंकर के माध्यम से सेनेटाईज करवाया। ट्रेक्टरों पर भी पीछे पानी की टंकी लगाकर मोटर से पाईप लगाकर सेनेटाईज कार्य हुआ। वहीं शहर के मुख्य स्थानों बस स्टेंड, राजवाड़ा, राजगढ़ नाका, मेघनगर नाका, दिलीप गेट पर तो फायर ब्रिगेड की मद्द से पूरे क्षेत्र को सेनेटाईज कर कोरोना से बचाव की दिशा में आमूलचूल प्रयास किए गए।

झाबुआ के मारूति नगर में ट्रेक्टर से सेनेटाईज करते नगरपालिका के कोरोना यौद्धा।

झाबुआ के वार्ड क्र. 2 में नगरपालिका के स्वच्छता अधिकारियों का किया सम्मान।

शहर की सफाई व्यवस्था भी चुस्त-दुरस्त

नगरपालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी निरंतर चुस्त-दुरस्त रखा है। सफाईकर्मियों द्वारा नियमित प्रातःकाल सड़कों की सफाई के साथ नाले-नालियों की भी सफाई का कार्य जारी है। नाले-नालियों में मच्छरों से प्रकोप से बचाव हेतु डीटीपी किटनाशक दवाई का छिड़काव भी समय-समय पर करवाया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक सुविधा घरों की सफाई के अतिरिक्त कूड़े-कचरे के ढ़ेर की भी सफाई कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।

कोरोना फायटरों का हो चुका है सम्मान

इसके फलस्वरूप ही नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी कुरैशी, स्वच्छता शाखा के प्रभारी जायसवाल तथा सहायक स्वच्छता निरीक्षक मलिया और पूरी सफाई टीम का पूरे शहर में जगह-जगह सम्मान भी हो चुका है। पिछले दिनों लक्ष्मीबाई मार्ग में वार्ड क्र. 5 के पार्षद नरेन्द्र संघवी के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई मार्ग मित्र मंडल द्वारा इन कोरोना फायटरों का स्वागत किया गया। शहर के वार्ड क्र. 2 में जाकिर कुरैशी के नेतृत्व में भी वार्ड के रहवासियों ने शाल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंटकर तथा पुष्पामाला पहनाकर पूरी स्वच्छता टीम का सम्मान कर जमकर तालियां बजाई।

जैन ने सीईओ जिला पंचायत के पद पर पदभार ग्रहण किया

माही की गूंज, झाबुआ। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया। जैन इसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में पदस्थ थें। जैन पूर्व में 3 जुलाई 2017 को प्रशिक्षण के दौरान झाबुआ का भ्रमण कर चुके हैं। जैन द्वारा कलेक्टर से सौजन्य भेंट की तथा जिला पंचायत अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। जिला पंचायत अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा जैन का अभिनंदन किया गया।

अच्छी बारिश के लिए बच्चों ने मिलकर मनाई उज्जयनी

माही की गूंज, झाबुआ। 15 जून मानसून की तिथि आने के बाद अब हर किसी को अच्छी बारिश का इंतजार है। प्रायः 15 जून बाद वर्षाकाल आरंभ हो जाता है। अच्छी बारिश की आस से किसान वर्ग आसमान की और टकटकी निगाहे लगाए हुए है। वहीं जिलेवासी भी अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। इसी बीच जोरदार तथा सत्त बारिश के लिए शहर के सिद्धेश्वर कॉलोनी में छोटे-छोटे बच्चों ने मिलकर उज्जयनी मनाई, अर्थात घर की छत पर दान-पानिये बनांए। कंडों पर दान-पानिये बनाकर बाद उन्हें समूह में बैठकर ग्रहण किया। लजीज दाल-पानियों का लुत्फ उठाने के साथ ही सभी बच्चों ने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की कि किसानों द्वारा अब खरीफ सीजन में बोवनी शुरू करने के लिए तथा वर्तमान में लग रहीं तेज गर्मी और उमस से निजात के लिए वर्षा का दौर सत्त शुरू हो। बच्चों ने स्वयं ही दाल-पानिये बनाकर उसका आनंद लिया। छोटू भदौरिया, अमन, अली शेख, सोनाक्षी गोलानी, बाबुभाई, दिव्यांशु गोलानी, वेद आदि ने मिलकर यह आयोजन किया।

करवड़ दुकान निर्माण मामले में अपर कलेक्टर के निर्देश पर जनपद सीईओ ने जारी किया स्टे

मामले को मीडिया में उठाने वाले पत्रकार को अज्ञात नंबरों से फोन कर दी धमकी, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

माही की गूंज, झाबुआ/पेटलावद।

ग्राम पंचायत करवड़ में बस स्टेंड पर चल रहे दुकान निर्माण मामले का विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ पूर्व में अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों को ग्राम पंचायत पक्की दुकान बना कर दे रही है। वहीं ग्राम पंचायत ने इसी भूमि पर 32 लोगों के लिए आवासीय पट्टे की स्वीकृति जिला कलेक्टर ने दे रखी हैं। जिन लोगों को दुकानें दी जाना है। उनमें कोई भी आवासीय पट्टाधारक नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन गामड़ ने मामले में अधिकारियों से शिकायत कर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। वही एमपीआरडीसी द्वारा दुकानें रोड़ की सीमा में बनाने का विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्य रोकने की मांग की थी। प्रशासन द्वारा जांच में ग्राम पंचायत की भारी लापरवाही सामने आई, लेकिन राजनीति और गुलाबी नोटों तले दबी प्रशासनिक व्यवस्था गलत को भी आंखे मुंद कर देखने के मजबूर हैं। मौके पर सीमांकन से लेकर निर्माण तक ग्राम पंचायत नियम कायदे ताक में रखते रही। जिला कलेक्टर से लेकर जनपद सीईओ द्वारा कार्य रोकने तक के निर्देश दिए, लेकिन लिखित स्टे के अभाव में कार्य रोकने के स्थान पर कार्य मे प्रशासन की मिली मोन स्वीकृति पर अधिक तेजी से कार्य शुरू कर दिया। जिसका शिकायतकर्ता पुरजोर विरोध करने और गूंज द्वारा लगातार मामले को उठाने के चलते शुक्रवार को अपर कलेक्टर झाबुआ के निर्देश पर जनपद सीईओ पेटलावद ने ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव को कार्य रोकने के लिखित आदेश जारी कर दिए। ग्राम पंचायत के सचिव गोपालदास बैरागी का कहना है कि सीईओ पेटलावद से प्राप्त पत्र के बाद कार्य रोकने का कहा था, लेकिन उप सरपंच ने अपनी हठधर्मिता के चलते कार्य नहीं रोका। अब जब तक प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलती, कार्य शुरू नहीं हो इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।

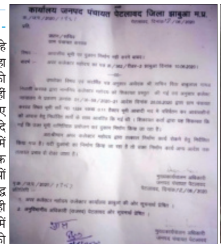

स्टे की कॉपी और हवा और बारिश से टूटा घटिया निर्माण ।

समाचार प्रकाशित करने पर प्रतिनिधि को दी धमकी, इंटरनेशनल नम्बरों से किया फोन

गूंज द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाया गया जिसे ग्राम करवड़ में बन रही दुकानों के कुछ दुकानदारों द्वारा अज्ञात नम्बरों से प्रतिनिधि को मामले में समाचार प्रकाशित नहीं करने धमकी दी गई। शातिर धमकी देने वाले यहीं नहीं रुके नम्बर ट्रेस होने के डर से किसी शातिर साइबर के जानकार के सहयोग से इंटरनेशनल नम्बर जनरेट कर धमकी दी गई। लगभग 05 से 07 अलग-अलग नम्बरों से धमकी भरे कॉल किए गए। मामले की शिकायत प्रतिनिधि द्वारा पेटलावद थाने में की गई हैं।

साइबर क्राइम से जुड़ा हो सकता कालर

जिस तरह से धमकी देने के लिए इंटरनेशनल नम्बरों का प्रयोग किया गया। उससे वर्तमान में फेसबुक आईडी हैक कर पैसे मांग कर लोगों को ठगने और ऐसे नम्बरों से लोगों को फोन कर आधार नम्बर और एटीएम कार्ड के नंबर लेकर खाते से पैसे उड़ाने वाले सक्रीय हैं। ऐसे अपराध साइबर के जानकार ही अंजाम दे सकते हैं। पुलिस यदि मामले में साइबर क्राइम ट्रेस करने वाली पुलिस की सहायता लेकर ईमेल पासवर्ड के जरिये कालर तक पहुंच जाए तो किसी बड़े अपराध, अपराधी या किसी साइबर क्राइम के ग्रुप से जुड़े व्यक्ति का भी खुलासा होने की संभावना है।

अनुमति का चल रहा है खेल

आवासीय पट्टे के निर्माण के कलेक्टर के आदेश को ताक में रख कर व्यवसायिक दुकान निर्माण के लिए अनुमति देने का खेल राजस्व विभाग में चल रहा है। यहां एसडीएम मालवीय छुट्टी पर है तो थांदला एसडीएम बघेल को चार्ज दिया गया है। जो खुद भी छुट्टी पर उतर गए, लेकिन ग्राम पंचायत के आवेदन पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई। कोई अधिकारी इसकी जानकारी के बारे में पुष्टि नहीं कर रहा है। शिकायतकर्ता सचिन गामड़ की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। वहीं आवासीय पट्टे हेतु जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन देकर पट्टे दिए जाने और दुकान निर्माण के कार्य को रोकने हेतु आवेदन दिया है।

डरने और रुकने वाली गूंज की कलम नही

धमकी देने वालों में शामिल लोगों या उनके पीछे खड़ी पंचायत या नेताओं को साफ शब्दों में हिदायत हैं कि वो किसी मुगालते में ना रहे। गूंज की कलम दबने और डरने वाली नहीं है। आगे और भी बड़े खुलासे और अधिकारियों की लेन-देन, नियमों को ताक में रख कर धोखाधड़ी कर सरकारी दस्तावेज तैयार करने के गंभीर खुलासे किए जाएंगे। जिन दुकानदारों को दुकानें मिलना है, हमें उनसे भी पूरी संवेदना हैं जो लाखों खर्च कर ग्राम पंचायत और कुछ नेता की लापरवाही, हठधर्मिता के कारण अब तक अपने रोजगार से दूर है, मामला अब न्यायालय तक जाना है। जहां जिला कलेक्टर से लेकर स्कूल विभाग और ग्राम पंचायत तक को जवाब देना होगा। जिनकी लापरवाही और रिश्वतखोरी की वजह से 34 दुकानदार और 32 आवासीय पट्टे धारकों को परेशान होना पड़ रहा है।

तीन सवारी और मुंह पर मास्क नही लगाने वालों पर कार्यवाही

माही की गूंज, झाबुआ।

नगर में यातायात विभाग द्वारा तीन सवारी बैठाकर दो पहियां वाहन चालकों की धरपकड़ शुरू की गई। जिसमें उनके द्वारा यदि मास्क को मुंह पर नहीं पहना है तो भी उन पर वाहनों को रोककर चालानी कार्यवाही की गई। नगर में इन दिनों लॉकडाउन के बाद मिली आंशिक छूट के बाद से लोगों के द्वारा कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरती जा रही है।। ऐसे में यातायात विभाग के द्वारा इस ओर पहल कर ऐसे बेवजह घूमने वालों के साथ ही मुंह पर मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

यातायात प्रभारी मुजाल्दा द्वारा बताया गया कि यह कार्यवाही सतत जारी रहेगी। सोमवार को विजय स्तम्भ चौराहा, छतरी चौक, के साथ ही डीआपी लाईन स्थित विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें यातायात विभाग के द्वारा तीन सवारी बैठाकर ले जा रहे व्यक्ति के साथ ही मुंह पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों की चालानी कार्यवाही में 500 रूपए की रसीद दी जा रही है। वहीं यह समझाईश दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण के समय सोश्यल डिस्टेसिंग का पालन कर मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से निकले। यदि अतिआवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले अन्यथा ना निकले। मुजाल्दा द्वारा बताया गया कि नगर में अभी यह कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

सोया हुआ है खनीज विभाग, रेत का अवैध उत्खनन कर नदी को कर दिया खोखला

सैकड़ों ट्रिप रेत रोज निकल रही नदी से , राजस्व के नाम पर सरकार को एक दमड़ी भी नही

माही की गूंज, पेटलावद।

राज्य सरकार की नई खनन नीति नही आने का लाभ इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन कर रहे लोगो ओर खनिज विभाग के अधिकारी चांदी का काट रहै हैं और शासन को लाखों रुपये रोज के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है । पेटलावद विकास खण्ड में रेत की खनिज विभाग में ऑफदी रेकॉर्ड दर्ज लगभग सभी खदानों से ट्रेक्टर ओर डम्फरो द्वारा रेत चोरी की जा रही है लेकिन बन्दी के पेसो की चादर ओर खनिज विभाग कुमकर्णी नींद सो रहा है ओर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे लोग बेरवाह हो कर नदी को खोखला कर रहे हैं , लगातार शिकायतो के बाद न राजस्व विभाग न ही खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे रहा है । वेसे तो विभाग की हर छोटी बड़ी खदान से रेत निकलने का कार्य हो रहा लेकिन ऐसी ही दो बड़ी रेत खदानों केशरपुरा ओर गरवाड़ा (गामड़ी) का मामला संज्ञान में आया जहाँ रोज के पचासो ट्रेक्टर बिना किसी रॉयल्टी या किसी शासकीय शुल्क चुकाए रोज भरे जा रहे है जिसकी जानकारी राजस्व ओर खनिज विभाग के अधिकारियों को भी है लेकिन इन अवैध उत्खनन करने वालो को रोकने वाला कोई नही एक्का दुक्का वाहनों को कभी कार्यवाही के नाम पर पकड़ा भी जाता है तो लेंन देंन छोड़ दिया जाता है । केशरपुरा ओर गरवाड़ा की खदान से माही किनारे से लेकर खवासा,भामल से रायपुरिया झकनावदा तक के ट्रेक्टरो द्वारा रोज जा रही हैं । खनिज अधिकारी झाबुआ की लापरवाही का आलम ये हैं कि कई बार फोन लगाए जाने के बाद भी न तो फोन अटेंड होता हैं न ही जानकारी पहुँचने के बाद कोई कार्यवाही ।

फोटो केसरपुरा ओर गामड़ी-गरवाड़ा से अवैध रेत खनन करते ट्रैक्टर ।

नहीं बनी नई खदान नीति

प्रदेश की रेत खदान नीति लम्बे समय से नही बनी हैं अटकी हुई है जिले में कोई रेत खदान का टेंडर नही हो सका हैं , पहले ठेका पद्धति थी बाद में ग्राम पंचायत को रॉयल्टी का काम दिया गया था 350 रुपये प्रति ट्रेक्टर रायल्टी शासन को थोड़ी बहुत भी लाभ हो रहा था लेकिन अब ऑनलाइन रायल्टी की प्रोसेस है लेकिन कोई रॉयल्टी ऑनलाइन नही कटवाता हैं जिससे शासन को नुकसान उठाना पड़ रहा हैं ।

आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जान से खेल रहे एमपीईबी के जवाबदार अधिकारी

माही की गूंज, खवासा।

जिले में करीब 4 सौ आउटसोर्सिंग कर्मचारी एमपीईबी विभाग में प्रतिमाह 7 हजार की तनख्वा पर कार्यरत है। उक्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी का कार्य लेबर का होकर लाइनमैन के साथ जाकर बिजली लाइन का कार्य करते समय निसहनी तोककर चलना, रस्सी को खींचना आदि कार्य साथ में रहकर करना होता है। बिजली लाइन के खम्बे पर लाइनमैन को ही अथोराइट है कि वह बिजली के खम्बे पर चढ़कर विधिवत व परमिट लेकर लाइन बंदकर कार्य करें। परंतु लाइनमैन सारे नियमों तथा जवाबदेही की धज्जियां उड़ाकर बिजली के खम्बे पर लाइन सुधार हेतु बिना किसी ट्रेनिंग व अनुभव विहीन 7 हजार की तनख्वा पाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बिजली के खम्बे पर चढ़ावाकर बिजली लाइन सुधारने का कार्य करवाया जाता है। इतना ही नहीं लाइनमैन व कनिष्ठ यंत्री की इतनी लापरवाही होती है कि बिना परमिट व बिना बिजली लाइन बंद किए ही अनुभवविहीन आउटसोर्सिंग कर्मचारी (लेबर) को बिजली के खम्बे पर चढ़ावाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण जिले में ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारी काल के ग्रास बन चुके हैं और उनका परिवार आज दुखी है। बावजूद उसके जवाबदार अधिकारी कोई नसीहत नहीं ले रहे और आए दिन आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ दुर्घटना, बिजली लाइन के कार्य करते समय थमने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारी हर एक दुर्घटना में सांठ-गांठ व प्रलोभन के साथ मामले को रफा-दफा कर देते है।

ऐसा ही कुछ मामला खवासा ग्रिड के सेमलिया-तलवाड़ा फिडर पर 10 जून को सामने आया। आउटसोर्सिंग कर्मचारी राजेश पिता सकरिया भूरिया को कनिष्ठ यंत्री निशांतसिंह के निर्देशन में लाइनमैन द्वारा बिना परमिट लिए चालू लाइन में ही बिजली लाइन सुधार हेतु फिडर पर कार्य करने हेतु भेज दिया। राजेश को लाईन सुधार का कार्य करने हेतु बिजली के खम्बे पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही राजेश खम्बे पर चढ़ा और तार छूते ही बिजली के करंट के झटके से अपने आपको छुड़ाकर धड़ाम से नीचे गिर गया। गिरने से राजेश पूरी तरह जख्मी हो गया और उसे बेहोशी की हालत में ही पेटलावद हॉस्पिटल में उपचार हेतु ले जाया गया। ऊपर वाले की यह कृपा रही कि राजेश की सांसे लौट आई और अभी खतरे से बाहर है। लेकिन इस दुर्घटना में अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही को जवाबदार नजरअंदाज कर ऐसी दुर्घटनाओं को ओर बढ़ावा ही दे रहे हैं। बता दें कि उक्त दुर्घटना को बिजली विभाग के रिकार्ड में दर्ज ही नहीं किया और न ही बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। राजेश को प्रलोभन व नौकरी का भय बताकर पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया गया। अधिकारियो की इन करतूतों के कारण दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारी को शासन की ओर से मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो जाते है।

सेमलिया फिडर पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण बुरी तरह जख्मी हुआ राजेश।

इस संबंध में राजेश भूरिया से बात की तो माही की गूंज को बताया कि, रतन चंद्रावत लाइन हेल्पर के कहने पर मैं और भेरू गरवाल दोनों आउटसोर्सिंग कर्मचारी लाइन सुधारने हेतु गए थे। भेरु गरवाल ने कहां कि परमिट लेकर लाइन बंद कर दी है। इसके बाद में बिजली के खम्बे पर चढ़ा और मेरे साथ भेरू भी खम्बे पर चढ़ा जैसे ही मैंने जंफर को पकड़ा वैसे ही मेरे हाथ में आग की लो लगने लगी और पीछे से भी जलने लगा। मैंने हिम्मत करके खम्बे पर दो लात मारी और नीम के पेड़ पर गिरते हुए जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कौन मुझे इलाज के लिए ले गए यह भी होश नहीं था। दुर्घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज बिजली विभाग ने नहीं करवाई। न ही जेई साहब ने आकर हाल जाना। लाइनमैन रतन चंद्रावत मेरा पूरा इलाज करवा रहा है।

जब इस संबंध में रतन चंद्रावत से बात की तो बताया, मैं संविदा लाइन कीपर हूं, मैं 33 केवी लाइन पर था। लाइनमैन भगतसिंह राठौर ने उन्हें कार्य करने हेतु भेजा था। कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। जबकि राजेश के अनुसार भगतसिंह राठौर उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं आया था। इस सम्बंध में जब जेई निशांतसिंह से बात करनी चाही तो लम्बे समय तक मोबाईल बंद ही बताता रहा।

बता दें कि डेढ़ वर्ष पूर्व भी सेमलिया फिडर पर ऐसी ही लापरवाही के कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारी सुखराम की लाइन सुधार का कार्य करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। वहीं मंगलवार को भी परवलिया में उमेश पाटीदार, परवलिया फिडर पर खम्बे पर लाइन सुधार हेतु चढ़ा था लेकिन बिजली चालू होने के कारण धड़ाम से नीचे गिरकर जख्मी हो गया। उक्त मामले को भी विभाग के अधिकारियों ने रफा-दफा कर दिया।

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साइबर बुलिंग का खतरा

भारत में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्कूल निकट भविष्य में खुल पाएंगे, इसकी संभावना घटती जा रही है। ऐसे में संभावना यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई का चलन जारी रहेगा, जो लॉकडाउन के दौरान प्रचलन में आया। ऑललाइन पढ़ाई से समाज में गैर-बराबरी बढ़ने जैसी चिंताएं पहले ही काफी जताई गई हैं। यह हकीकत है कि देश में ज्यादातर आबादी के पास आज भी फास्ट वाईफाई से संचालित इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्ट फोन या लैपटॉप उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, जिनके पास ये उपलब्ध हैं, उनके घरों के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई में जोखिम कम नहीं हैं। बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) के हाल में दिल्ली में किए गए सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान कम से कम सवा 9 फीसदी बच्चों ने साइबर बुलिंग का अनुभव किया। लेकिन उनमें से आधे बच्चों ने कभी इसके बारे में माता-पिता या किसी बड़े को नहीं बताया। इसी सर्वे में ये भी सामने आया कि बच्चे जितना ज्यादा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, उतना ही ज्यादा उन पर साइबर बुलिंग जैसी प्रवृत्तियों का खतरा रहता है। सर्वे में पाया गया कि 13 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे दिन में तीन घंटे से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, उनमें बुलिंग जैसी घटनाओं का सामना करने वालों की संख्या 22 फीसदी थी। वहीं चार घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में यह संख्या छह फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी तक थी। इस स्टडी से एक और डराने वाला आंकड़ा निकल कर आया। सर्वे में शामिल बच्चों में 10 में से चार लड़कों ने अपनी मॉफर्ड यानी बदली तस्वीर या वीडियो देखी। इनमें से आधे बच्चों ने कभी पुलिस में इस बात की शिकायत नहीं की। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आज बच्चे जिस तरह टेक्नोलॉजी से भरे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वैसा माहौल उनके माता-पिता ने अपने बचपन में नहीं देखा था। इसलिए ऑनलाइन सही आदतें क्या हैं, क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं, लोगों से क्या और कैसे बात करनी चाहिए, किन वेबसाइट्स पर जाना चाहिए और किन पर नहीं, पोस्ट करते वक्त सही भाषा का इस्तेमाल जैसे कई टॉपिक्स पर माता-पिता से बच्चों की बात नहीं होती। जबकि साइबर बुलिंग जैसे खतरों से सिर्फमतापा-पिता ही बचा सकते हैं। जो साफहै कि ऑनलाइन पढ़ाई आगे बढ़ती है, तो अभिभावकों को ये विशेष जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422